सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
YouTube
RNI No :- DELHI/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 275, नई दिल्ली । शनिवार, 14 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज किया
06 भारत को एक स्वास्थ्य सेवा, एक शिक्षा की आवश्यकता है
08 ओलंपियन दुति चाद की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई

दिल्ली के व्यवसायिक वाहनों के मालिकों ने दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें दिल्ली में वाहन जांच में आ रही परेशानियों से अवगत करवा कर मदद की गुहार लगाई

संजय बाटला

नई दिल्ली। संजीव झा एम.एल.ए. बुराड़ी के नेतृत्व में दिल्ली के वाहन मालिकों/चालकों और कारोबारियों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से दिल्ली सचिवालय में मुलाकात की। दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिकों ने मुख्यमंत्री को परिवहन आयुक्त द्वारा बिना सोचे समझे और बिना पूर्ण जानकारी प्राप्त किए जारी किए आदेश से व्यवसायिक वाहन मालिकों और कारोबारियों को आ रही परेशानियों से अवगत करवाया और उनसे इसके लिए जल्द से जल्द समाधान निकलवाने की गुहार लगाई।

मुख्यमंत्री से मुलाकात में संजीव झा एम.एल.ए. बुराड़ी के साथ केके छाबड़ा, राजू कक्कड़, विनोद नेगी, देवेंद्र यादव और सुभाष त्यागी उपस्थित थे। 20 मिनिट की इस मुलाकात में मुख्यमंत्री आतिशी को बताया गया

2018 में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर भी बुराड़ी से वाहन जांच बंद करवाकर झूलझूली वाहन जांच शाखा में स्थानांतरित कर दी गई थी और कुछ ही महीनों में स्वयं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आदेश जारी कर वापिस बुराड़ी वाहन जांच शाखा में शुरू करवा दी थी क्योंकि तभी यह सिद्ध हो गया था की झूलझूली वाहन जांच शाखा में दिल्ली के सभी व्यवसायिक वाहनों को जांच करने की क्षमता नहीं है और उस क्षेत्र में वाहन मालिकों और वाहनों की सुरक्षा भी नहीं है और अब परिवहन आयुक्त द्वारा बिना दिल्ली की जनता को प्राप्त होने वाले व्यवसायिक गतिविधि में शामिल वाहनों की सेवा से वंचित करने और वाहन मालिकों की रोजी रोटी रुकवाने का कृत्य करते हुए बिना पूर्व व्यवस्था किए आदेश जारी किए हैं और इस बात की जानकारी उस दिन पद पर कार्यरत उपायुक्त वाहन जांच एवम् उपस्थित उपायुक्त रामनाथन को थी फिर भी एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य के लिए आदेश जारी कर दिए गए। इसके अलावा

1. झूलझूली वाहन जांच शाखा में इतने वाहनों को जांच करने की क्षमता ही नहीं है जितने वाहनों को वहां वाहन जांच के आदेश जारी किए गए

2. झूलझूली वाहन जांच शाखा में वाहन मालिकों/ चालकों और वाहनों की सुरक्षा भी नहीं है जिसके बारे मे दिल्ली पुलिस तक को जानकारी है

3. झूलझूली वाहन जांच शाखा में परिवहन अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जान सुरक्षित नहीं है जिस कारण काई अधिकारी वीआरएस तक दे चुके है और परिवहन विभाग द्वारा 2 एफआईआर भी दर्ज करवाई जा चुकी हैं

4. झूलझूली वाहन जांच शाखा में जिस कंपनी द्वारा एटीएस संयंत्र लगाया हुआ है उसका टेंडर खत्म हुए काफ़ी समय हो चुका है और परिवहन आयुक्त द्वारा बार बार एक्टेंशन मिलने प्राप्त कर के काम कर रही हैं

5. बुराड़ी वाहन जांच शाखा में अनगिनत एटीएस संयंत्र और उसके चलने के लिए आवश्यक पूरा सिस्टम उपलब्ध है फिर भी परिवहन आयुक्त उसको शुरू करवाने की जगह झूलझूली वाहन जांच शाखा में कार्यरत कंपनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से एक्सटेंशन देकर क्षमता से अधिक वाहनों को वहां भेजकर वाहन मालिकों को परेशानियों में धकेल रहे है

6. आज दिल्ली के व्यवसायिक वाहनों को परिवहन आयुक्त द्वारा जारी इस आदेश के कारण वाहन जांच की अपॉइंटमेंट तक भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं और बिना वाहन जांच प्रमाण पत्र के सड़को पर वाहन नहीं चला पा रहे और जुर्माने के साथ भुखमरी के कगार पर पहुंचाते जा रहे है।

मुख्यमंत्री ने सभी तथ्यों को सुनने और सबूतों के साथ समझने के बाद 7 दिन के अंदर ही इस समस्या का समाधान करवाने का वायदा दिया।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

सरकार की नई योजना: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से मिलेगी राहत, फ्लेक्स-फ्यूल से कार चलाना होगा सस्ता

परिवहन विशेष न्यूज

नईदिल्ली। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान आम आदमी के लिए राहत की खबर है। सरकार ने फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, जिससे वाहन मालिकों को प्रति लीटर ईंधन की लागत में कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में संकेत दिए हैं कि वैकल्पिक ईंधन से चलने वाली कारों पर जीएसटी कम करने की योजना है, जिससे इन वाहनों की कीमतें कम होंगी और ईंधन की लागत भी घटेगी।

फ्लेक्स-फ्यूल क्या है?

फ्लेक्स-फ्यूल एक प्रकार का ईंधन है, जिसमें पेट्रोल के साथ एथनॉल या मेथनॉल मिलाया जाता है। यह ईंधन पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है और वाहन की कार्यक्षमता में भी सुधार करता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि पेट्रोल में 60% एथनॉल और 40% बिजली का उपयोग किया जाए, तो इसकी कीमत 20 रुपये प्रति लीटर तक हो सकती है।

सरकार की तैयारी

वर्तमान में कुछ पेट्रोल पंपों पर फ्लेक्स-फ्यूल उपलब्ध है। सूत्रों के अनुसार, इस वर्ष के अंत तक देश के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर एथनॉल युक्त पेट्रोल उपलब्ध होगा, जिससे वाहन मालिकों को प्रति किलोमीटर लागत में आधी कमी का लाभ मिलेगा।

सरकार की यह पहल पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने में सहायक होगी। फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक के माध्यम से वाहन मालिकों को सस्ती और पर्यावरण-मित्र ईंधन उपलब्ध होगा, जिससे उनकी यात्रा लागत में कमी आएगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

दिल्ली में इन गाड़ियों पर हो रहा धड़ाधड़ एक्शन, ट्रैफिक पुलिस कर रही जब्त

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली परिवहन विभाग ने एक बार फिर जनता को चेताया है कि वे अपने उम्र पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप करा लें या दूसरे राज्य में पंजीकरण कराएं। अन्यथा सड़कों पर पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। अब तक दिल्ली में 59 लाख से अधिक वाहनों को डी-रजिस्टर्ड किया जा चुका है लेकिन फिर भी लोग उन्हें चला रहे हैं।

नई दिल्ली। परिवहन विभाग ने जनता को फिर चेताया है कि उम्र पूरी कर चुके अपने वाहन को स्क्रैप करा लें या दूसरे राज्य में पंजीकरण कराएं।अन्यथा सड़कों पर मिला तो जब्त कर लिया जाएगा।

सार्वजनिक सूचना जारी कर कहा कि दिल्ली में अब तक 59 लाख वाहन डी-रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं।मगर फिर भी लोग उन्हें चला रहे हैं। बता दें कि परिवहन विभाग उम्र पूरी कर चुके वाहनों को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर चुका है।

वाहनों की संख्या 59 लाख के पार

एसओपी से यह बात साफ की गई है कि दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों की संख्या 59 लाख के पार पहुंच गई है। फाइनल दिशा निर्देश में विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि उम्र पूरी कर चुके वाहन को खड़ा रखने की अनुमति उसी दिशा में दी जाएगी जिनके पास अपने घर में वाहन के लिए पार्किंग है।

मगर वे उस वाहन को घर से बाहर नहीं निकाल सकेंगे। सार्वजनिक पार्किंग या घर के बाहर खड़ा ऐसा मिलता है तो उसे उठा लिया जाएगा। पकड़े जाने पर वाहन को छोड़े जाने का प्रविधान केवल पहली बार के लिए मान्य होगा।

गाड़ियों को जब्त करके स्क्रैप करने का प्रविधान

एसओपी से यह बात साफ की गई है कि दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों की संख्या 59 लाख के पार पहुंच गई है। फाइनल दिशा निर्देश में विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि उम्र पूरी कर चुके वाहन को खड़ा रखने की अनुमति उसी दिशा में दी जाएगी जिनके पास अपने घर में वाहन के लिए पार्किंग है।

अगर दूसरी बार वही वाहन फिर से सड़क पर पाया जाता है तो उसे जब्त कर सीधे स्क्रैप करा दिया जाएगा।दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में डीजल की 10 साल और पेट्रोल की 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के चलाने पर पाबंदी है। ऐसी गाड़ियों को जब्त करके स्क्रैप करने का प्रविधान है।

हालांकि, अगर कोई व्यक्ति अपने उम्र पूरी कर चुके वाहन को दिल्ली के बाहर किसी अन्य राज्य में पंजीकरण कराना चाहता है तो उसके लिए प्रविधान हैं। साथ ही स्क्रैप डीलरों के लिए भी नियम बने हुए हैं। परिवहन विभाग की स्क्रैपिंग सेल के विशेष आयुक्त ने अब गत 20 अक्टूबर को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं।

केंद्रीय मंत्री गडकरी बोले- सड़क दुर्घटनाओं के लिए लोगों का व्यवहार जिम्मेदार

गडकरी ने कहा कि हर साल लाखों लोग सड़क हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। हम प्रतिभाशाली डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी खो देते हैं। इन सबका कारण लोगों का गलत व्यवहार है। उन्होंने कहा कि मानव व्यवहार को बदलना बहुत कठिन है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क हादसों में भारत का पहले स्थान पर आना गर्व का नहीं चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि देश के लिए यह गर्व का विषय है कि हमारे पास वैश्विक स्तर की सड़कें मिल चुकी हैं। लोगों के पास पैसा है और वे अच्छी-अच्छी गाड़ियां खरीद रहे हैं। लेकिन वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल दुर्घटनाओं को बढ़ा रहा है। लेकिन इसके बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। यह दुर्भाग्य का विषय है। गडकरी ने आईआईएसएसएम के ग्लोबल कॉन्क्लेव में आज ये बात कही।

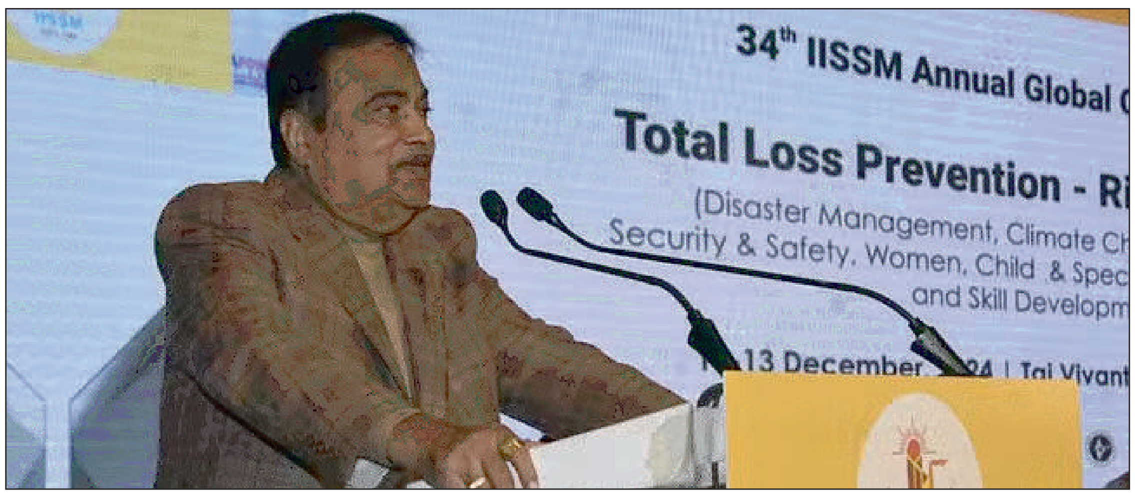

गडकरी ने कहा कि हर साल लाखों लोग सड़क हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। हम प्रतिभाशाली डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी खो देते हैं। इन सबका कारण लोगों का गलत व्यवहार है। उन्होंने कहा कि मानव व्यवहार को बदलना बहुत कठिन है। बड़े पैमाने पर लोगों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। लोग वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना नहीं छोड़ते। लोग हर बात जानने के बाद भी हेलमेट नहीं पहनना चाहते।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुरक्षा कई क्षेत्रों से जुड़ी है, लेकिन हमें सड़क सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यह हमारे देश के 1.5 लाख लोगों को हर साल हमसे छीन लेता है। हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है, कुशल इंजीनियरों को तैयार करना है और दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़कें-गाड़ियां बनानी हैं। लेकिन इसके लिए लोगों को अपना व्यवहार भी बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रबंधन, प्रशिक्षण और अनुसंधान कभी रुकना नहीं चाहिए।

इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. आरके सिन्हा ने कहा कि वे स्कूली स्तर से छात्रों को सड़क नियमों का प्रशिक्षण देकर जागरूक करने के लिए काम शुरू कर रहे हैं। सड़कों की सुरक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक कर सबसे बेहतर बदलाव किया जा सकता है। इससे देश की भावी पीढ़ी सड़कों पर चलने के समय ज्यादा सतर्क और गंभीर रहेगी। इससे आने वाले समय में इस तरह के हादसों को रोकने में मदद मिलेगी।

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कब होगा चालू? नितिन गडकरी ने दी जानकारी

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पूरा होने से दोनों महानगरों के बीच यात्रा का समय वर्तमान 24 घंटे से घटकर 12 घंटे रह जाने की उम्मीद है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि दिल्ली-देहरादून राजमार्ग परियोजना के दो पैकेज हैं।

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे अगले तीन महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर दो घंटे रह जाएगा। फिलहाल दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय पांच से छह घंटे है।

दिल्ल्ली में इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 को संबोधित करते हुए गडकरी ने आगे कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण दो महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। एक्सप्रेसवे के पूरा होने से दोनों महानगरों के बीच यात्रा का समय वर्तमान 24 घंटे से घटकर 12 घंटे रह जाने की उम्मीद है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि दिल्ली-देहरादून राजमार्ग परियोजना के दो पैकेज हैं।

गडकरी ने कहा, "दिल्ली के कालिंदी कुंज के लिए 10,000 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है, जो फरीदाबाद तक विस्तारित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 15-20 दिनों के भीतर इस परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं।" गडकरी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार वायु प्रदूषण को कम करने, जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने और कृषि आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, "परिवहन मंत्रालय वायु प्रदूषण के 40 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है... जबकि प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के कारण है, सड़क निर्माण और जीवाश्म ईंधन भी वार्षिक समस्या में इजाफा करते हैं।" मंत्री ने यह भी बताया कि पराली जलाने की समस्या दो साल में हल हो जाएगी। क्योंकि सरकार 400 परियोजनाओं पर काम कर रही है, जो हर साल 200 लाख टन चावल के भूसे को वैकल्पिक ईंधन में बदल देंगी। गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे पर काम कर रहा है। जिससे देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, "भारत की लॉजिस्टिक्स लागत 14-16 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह 8 प्रतिशत, अमेरिका और यूरोपीय संघ में 12 प्रतिशत है। हमारा लक्ष्य इसे दो वर्षों में 9 प्रतिशत तक लाना है।" मंत्री के अनुसार, इससे भारत के निर्यात में 1.5 गुना बढ़ोतरी होगी और हमें ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी। भारत में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के बारे में गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। जहां खराब सड़कों, कानून के खराब क्रियान्वयन और शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण प्रति वर्ष 5,00,000 दुर्घटनाओं में 1,78,000 मौतें होती हैं। गडकरी ने माना, "पिछले 10 वर्षों में कड़ी मेहनत के बावजूद हम देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सफल नहीं हुए हैं।"

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी ब्लैक स्पॉट को ठीक करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए बोली मानदंडों में बदलाव करने संबंधी उनके मंत्रालय की हालिया पहल से देश में दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी।

शादी के लिए कर रहे हैं किसी को डेट, तो रिश्ते पर मुहर लगाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

शादी जिंदगीभर का एक रिश्ता होता है जिसके लिए सोच-समझकर फैसला लेना चाहिए। खासकर जब बात लाइफ पार्टनर को चुनने की हो तो कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप शादी के इरादे से किसी को डेट कर रहे हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। आइए जानते हैं कौन-सी हैं वो बातें।

शादी एक जिम्मेदारी भरा रिश्ता होता है, जिसके लिए सोच-विचार बेहद जरूरी है। खासकर जब बात लाइफ पार्टनर की आती है, तो किसी को भी अपना हमसफर चुनने से पहले एक नहीं सौ बार सोचना और उसे परखना जरूरी है। शादी जिंदगीभर का रिश्ता होता है, जिसमें किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि एक छोटी-सी गलती या गलत फैसला न सिर्फ आपका रिश्ता खराब कर सकता है, बल्कि जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है।

इन बातों का रखें ध्यान-

शादी चाहे अरेंज हो या लव, इन बातों का ध्यान दोनों की कंडीशन में रखना जरूरी है। खासकर अगर आप शादी के इरादे से किसी को डेट कर रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आइए जानते हैं इन जरूरी बातों के बारे में-

शादी के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले एक-दूसरे से अच्छे जान लें। इसके लिए न तो बहुत कम समय लें न ही बहुत ज्यादा समय लगाएं। शादी करने के लिए 3-6 महीने का डेटिंग रूल जरूर फॉलो करें।

जब तक आप अपने रिश्ते को लेकर आश्वत न हो और इसे कोई ऑफिशियल स्टेटस न मिल जाए, तब तक शारीरिक संबंध न बनाएं।

अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो हेल्दी फ्लर्ट आम बात है, लेकिन ज्यादा फ्लर्ट न करें या सेक्सटिंग में शामिल न हों।

अपने पार्टनर से बात करते समय किसी अपेक्षा न रखें। साथ ही अपनी डेस्पिरेशन पर भी काबू रखें।

अपने रिश्ते को सीरियस स्टेज पर ले जाने के लिए 10-12 डेट्स के बाद पेरेंट्स को इसमें शामिल करें। आप चाहें कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हैं या फिर उनसे पर्सनली मिल सकते हैं। आप चाहें तो इसके बाद कुछ समय ले सकते हैं।

सिर्फ चैटिंग करने की बजाय ऑफलाइन मिलें, क्योंकि यह जरूरी है। साथ ही एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए चैटिंग से ज्यादा कॉल और वीडियो कॉल का सहारा लें।

अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो कम से कम 3 से 6 महीने में 8-10 बार मिलें, जब तक कि आप कोई फैसला न ले लें। अगर आप आप एक ही शहर में हैं, तो 3-6 महीने तक हर हफ्ते कम से कम एक बार मिलें, ताकि फैसला लेने से पहले आप एक-दूसरे को समझ सकें।

मीटिंग कैजुअल कॉफी डेट की तरह नहीं होनी चाहिए। घंटे-दो घंटे बैठकर कुछ खा-पीकर वापस घर चले जाने से एक-दूसरे को समझने में मदद नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको कम से कम आधे दिन साथ रहना चाहिए। आप इसके लिए किसी पार्क, संग्रहालय, चिड़ियाघर, समुद्र तट, पहाड़, मंदिर या किसी अन्य स्थान पर एक-साथ समय बिता सकते हैं।

शादी के बाद भी क्यों जरूरी है सोलो ट्रिप फायदे जानकर हैरान रह जाएंगी महिलाएं

सोलो ट्रिप्स पर जाना हर कसिी का सपना होता है। पार्टनर और बच्चों के साथ समय बिताना जरूरी है लेकिन खुद के लिए समय निकालना भी उतना ही जरूरी है। महलिाओं को खासकर शादी के बाद सोलो ट्रपि पर जरूर जाना चाहिए। इससे आप कुछ समय तक अपने लिए जी पाएंगी। खुद को अच्छे से जान पाएंगी।

पछिले कुछ समय से लोगों में सोलो ट्रैवलगि का क्रेज काफी बढ़ गया है। सोशल मीडयिा पर भी कई वीडयिोज वायरल होते रहते हैं। सोलो ट्रैवलिंग का मतलब होता है अकेले घुमक्कड़ी करना। नई-नई संस्कृतयिों को करीब से जानना। आज दुनयिा में सोलो ट्रपि (Solo Trip Benefits) को लेकर लोग काफी एक्साइटेड होते हैं। क्योंकि इस दौरान आप अपने मन के मालकि होते हैं। आपका जहां मन करता है वहां घूमते हैं। जो मन करता है वो बनिा रोक-टोक के करते हैं। इसके बढ़ते ट्रेंड का एक कारण बिजी लाइफस्टाइल भी है। ऐसे में लोगों को खुद के लए़ि समय नकिालना मुश्किल हो रहा है।

अगर आप शादीशुदा (After Marriage Women Solo Trip Benefits) और बाल-बच्चे वाली भी हों तो भी आपको सोलो ट्रपि पर जरूर जाना चाहए़ि। ये आपके लए़ि कई तरह से फायदेमंद हो सकती है। आज हम आपको अपने इस लेख में बताएंगे कमिहलिाओं (Solo Trips For Women) को शादीशुदा होने के बाद भी क्यों सोलो ट्रपि पर जाना चाहए़ि। आइए जानते हैं वस्तिार से-

खुद को समझने का मौका

शादी के बाद महलिाएं अपने लिए तो जीना ही बंद कर देती हैं। घर, पत,ि बच्चे या ऑफसि उन्हें खुद के लए़ि समय नकिालने ही नहीं देते हैं। ऐसे में उन्हें रूटीन से हटकर अपने लए़ि सोचना चाहए़ि। इसके लए़ि घूमने से बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। आप सोलो ट्रपि के लए़ि अपनी कोई पसंदीदा जगह चुन सकती हैं। आप यहां अपने आपको पूरा समय दे सकती हैं। इससे आपकी ट्रिप भी यादगार हो जाएगी और आप खुद में नई ताजगी का अनुभव भी करेंगी।

मेंटल हेल्थ होता है बेहतर

शादी के बाद लाइफ में बहुत सारे बदलाव देखने को मलिते हैं। कई बार महिलाएं मेंटली डस्टिर्ब हो जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि वो मानसकि शांत‌ि पाने के लए़ि सोलो ट्रैवल करें। यह आपको अपनी चिंताओं और तनाव से दूर ले जाती है। प्रकृति के बीच समय बिताएं। नई चीजें सीखें। ये सब आप में नई ऊर्जा भर देगा।

आत्मविश्वास होता है मजबूत

महिलाओं को Self Confidence के लिए सोलो ट्रपि पर जरूर जाना चाहए़ि। शादी के बाद आप पत‌ि पर नर्भिर रहने के बजाय अकेले घूमने की प्लानिंग कर सकती हैं। इससे आपका आत्मवश्विास भी बढ़ेगा।

नई चीजें सीखने का मौका

महलिाओं को सोलो ट्रिप्स पर इसलए़ि भी जाना चाहए़ि ताकि वे नई संस्कृति, भाषा और खानपान का अनुभव कर सकें। किसी नई जगह को खुद से एक्सप्लोर करना और अपने डर पर काबू पाना आपको अंदर से मजबूत कर देता है।

गिल्ट में न रहें

महलिाओं को लगता है कि परिवार और बच्चों को छोड़कर सोलो ट्रिप पर जाना स्वार्थी हो सकता है, लेकनि ऐसे में आपको स्वार्थी होना पड़ेगा। आपके बारे में सर्फि आप ही सोच सकती हैं। आप सोलो ट्रपि पर जाकर कुछ दिन अपने हसिाब से जी सकती हैं।

दिल्ली की चुनावी जंग में कौन सत्ता का ताज पहनेगा?

ललित गर्ग

दिल्ली में भाजपा के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण होने के साथ संघर्षपूर्ण भी है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में, जहां पार्टी को शानदार प्रदर्शन की उम्मीद थी, उसे आम आदमी पार्टी से हार का सामना करना पड़ा।

दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए फरवरी 2025 या उससे पहले चुनाव होने की संभावनाओं को देखते हुए राजनीतिक हलचलें एवं सरगर्मियां उग्र हो गयी है। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की तैयारी में जुट गई है। वहीं, भाजपा और कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी है। भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव दूसरे प्रांतों की ही भांति बिना किसी मुख्यमंत्री चेहरे के लड़ने का मन बना चुकी है और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच रखेगी। पार्टी का मानना है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली में भाजपा के पास एक से एक मजबूत नेता हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नेता मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी के लिए पेश नहीं किया जा रहा है। भाजपा दिल्ली में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नए तरीके से चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है, वहीं कांग्रेस अपनी खोयी जमीन को हासिल करने के लिये जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित ही इस बार का दिल्ली चुनाव आक्रामक एवं संघर्षपूर्ण त्रिकोणात्मक होगा। आप, कांग्रेस एवं भाजपा की चुनावी जंग में कौन सत्ता का ताज पहनेगा, यह भविष्य के गर्भ है।

दिल्ली में भाजपा के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण होने के साथ संघर्षपूर्ण भी है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में, जहां पार्टी को शानदार प्रदर्शन की उम्मीद थी, उसे आम आदमी पार्टी से हार का सामना करना पड़ा। तब भाजपा को दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत करने से कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ। इसके बजाए, भाजपा अब चुनावी रणनीतियों में बदलाव कर रही है और अपनी शक्ति को पार्टी संगठन और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी लोककल्याणकारी योजनाओं के बल पर मजबूत करने का प्रयास कर रही है। यही कारण है कि दिल्ली भाजपा आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में केंद्र सरकार के काम और योजनाओं को जनता के बीच रखेगी। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि दिल्ली के लोग इससे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, खासकर जब बात विकास, सुरक्षा, चिकित्सा और शिक्षा जैसे मुद्दों की हो। अगर भाजपा बिना किसी प्रमुख चेहरे के चुनाव लड़ती है तो यह असमंजस की स्थिति बनने की संभावनाएं तो पैदा कर ही सकती हैं। दूसरी ओर, यह फैसला एक रणनीतिक कदम हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके अन्य प्रांतों की भांति दिल्ली में भी चमत्कार घटित हो सकता है।

भाजपा ने यह भी तय किया है कि दिल्ली की जनता को बताया जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ वादाखिलाफी की है, वे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और सड़कों की स्थिति में सुधार का वादा करके उन्हें जर्जर करते रहे हैं। भाजपा का मानना है कि मोदी सरकार की योजनाएं देशभर में सफलता प्राप्त कर रही हैं और इन्हें दिल्ली में लागू किया जाएगा। भाजपा को दिल्ली में हमेशा मिडिल और हाई मिडिल क्लास के लोगों की पार्टी माना जाता है। इसमें व्यापारिक समुदाय इसके कट्टर समर्थक हैं। लेकिन इस बार निचले तबको एवं गरीब लोगों के बीच उसे प्रभावी प्रयास करने होंगे। यह तो दिखता हुआ सच है कि दिल्ली में आप शासन में विकास अवरूद्ध हुआ है, पर्यावरण की समस्या उग्रतर हुई है, आप नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे एवं उनके नेता जेल यात्राएं की है। ऐसे अनेक गंभीर आरोपों के साथ भाजपा आप और उसके नेताओं पर आक्रमक होकर चुनावी परिदृश्यों को बदल सकती है।

भाजपा ने कमर कस ली है और उसके नेता लगातार जनता के बीच जाकर बदलाव की अपील कर रहे है। इसके तहत इन दिनों जहां परिवर्तन सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, वहीं अगले हफ्ते से पूरी दिल्ली में परिवर्तन यात्राएं भी निकाली जाएंगी। इन यात्राओं के माध्यम से आम मतदाताओं से निजी तौर पर मिलते हुए, उनसे बात करते हुए उनको पार्टी के साथ जोड़ा जायेगा। उनके दुःख-दर्द को सुना जायेगा। भाजपा का इतिहास रहा है कि वह आम जन तक पहुंचने के लिए ऐसी यात्राएं निकालती रही है एवं व्यक्तिगत संवाद स्थापित करती रही है। भाजपा नेता सतीश उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली में एक भ्रष्ट सरकार चल रही है लेकिन अब तो रंगदारी, वसूली, फिरौती और आम नागरिकों के बीच डर पैदा करने की भी कोशिश की जा रही है। इसके चलते दिल्ली की जनता अब सत्ता परिवर्तन के मूड में है और देशविरोधी मानसिकता वाली सरकार को इस बार विधानसभा से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। देखना है कि भाजपा के इन आरोपों का जनता पर कितना असर होता है।

निश्चित ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जमीन अभी भी मजबूत है। इसीलिये 2025 के चुनाव कांग्रेस एवं भाजपा के लिये चुनौतीपूर्ण होने वाले है। 2020 में हुआ विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थीं। वहीं भाजपा को महज 8 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस का लगातार दूसरी बार दिल्ली से सफाया हो गया था। इस बार के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद आतिशी मार्लेना राज्य की मुख्यमंत्री बनी हैं। आप नेताओं ने चुनाव अभियान प्रारंभ कर दिया है। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने का फैसला किया है। आप ने पिछले दो विधानसभा चुनावों में भारी अंतर से जीत हासिल की है। आप के आंतरिक सर्वेक्षण बताते हैं कि आप इस चुनाव में भी आसानी से जीत की ओर बढ़ रही हैं। इन स्थितियों में आप क्यों कांग्रेस या अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करें? आप अभी भी निम्न-मध्यम वर्ग और झुग्गी-झोपड़ियों वाले इलाकों में काफी लोकप्रिय है।

आप का वोट शेयर पहले की तुलना में बढ़ा है और कांग्रेस कमजोर हुई है। हालांकि, 2013 में अपने पहले चुनाव के बाद से आप का वोट शेयर लगातार बढ़ता रहा। जबकि पिछले दशक में कांग्रेस को वोट देने वालों की संख्या में काफी कमी आई है। आप ने 2013 में अपने आश्चर्यजनक प्रदर्शन के साथ, कुल मतदान का 29 प्रतिशत वोट प्राप्त किया था। पार्टी को 70 में से 28 सीटों पर जीत मिली थी। आप ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई थी। इससे कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 24.5 प्रतिशत और सिर्फ आठ सीटों के साथ तीसरे स्थान पर आ गई थी। इसके बाद 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर क्रमशः 9.7 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत तक गिर गया। वहीं, आप ने 54.6 प्रतिशत और 53.6 प्रतिशत वोट शेयर के साथ भारी जनादेश हासिल किया। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एवं आप के बीच गठबंधन न होने का फायदा भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है। असल में आप के वोट कांग्रेस ही काटेगी।

कांग्रेस एक पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसका दिल्ली में व्यापक जनाधार रहा है। लेकिन वह 'जीत' और 'गठबंधन' की मृगमरीचिका में भटकती रही है, अपनी स्वतंत्र पहचान को खोती रही है। आखिर कमजोर सियासी बैशाखियों के सहारे वह कैसे जीत को सुनिश्चित कर सकती है? कांग्रेस की एक ओर बड़ी विडम्बना है कि वह जरूरी मुद्दों को उठाने की बजाय मोदी-विरोध का ही राग अलापती रही है। मुद्दों के बियाबान में भटकती और फिर स्टैंड बदलती नजर आती है तो इसके केन्द्रीय नेतृत्व एवं रणनीतिकारों पर तरस आती है। जबकि कांग्रेस के जमीनी नेताओं के पास रणनीति और जनाधार दोनों है, इसलिए उसके जमीनी नेता व्यक्तिवादी मिशन में सफल रहे, लेकिन कांग्रेस दिन ब दिन डूबती चली गई। राजनीतिक परिस्थिति वश कभी दो डग आगे तो चार कदम पीछे चलने को अभिशप्त हो गई। इन स्थितियों में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई करिश्मा या चमत्कार कर पायेगी, इसमें संदेह ही है।

क्या आपका रिश्ता भी एक ही पहिए पर चल रहा है? ऐसे पता करें आप कर रहे हैं रिश्ते में ज्यादा इंवेस्ट

किसी भी रिश्ते को सफल बनाने के लिए दोनों पार्टनर्स को बराबर योगदान देना होता है। अगर आप ही रिश्ते में ज्यादा इंवेस्ट कर रहे हैं तो धीरे-धीरे आप नाखुश रहने लगेंगे और आपका रिश्ता भी कमजोर होने लगेगा। एक तरफा कोशिश के कुछ संकेत (One-sided Relationship Signs) होते हैं जिनकी मदद से आप यह पहचान सकते हैं कि कहीं आप ही तो रिलेशनशिप में ज्यादा इंवेस्ट नहीं कर रहे।

नई दिल्ली। क्या आपका रिश्ता आपको खुशी और संतोष देता है या आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बदले में उतना नहीं मिल रहा? अगर आप इस सवाल पर सोच में पड़ गए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने रिश्ते में अपने पार्टनर से ज्यादा इंवेस्ट कर रहे हों।

यह समझना जरूरी है कि हर रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और कभी-कभी हमें अपने पार्टनर के लिए थोड़ा ज्यादा करना पड़ सकता है (Relationship Investment Tips), लेकिन अगर यह स्थिति लगातार बनी रहती है, तो यह आपके लिए भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है। इस कंडीशन में रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं पाता है और आप खुद भी अंदर से खुश नहीं रहते हैं। इसलिए हम यहां कुछ ऐसी बातें (One-sided Relationship Signs) बता रहे हैं, जो इस तरफ इशारा करती हैं कि आप अपने रिश्ते में अपने पार्टनर से ज्यादा इंवेस्ट कर रहे हैं।

आप अपनी जरूरतों को अनदेखा कर रहे हैं

अपनी हॉबीज को छोड़ना- अगर आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए अपनी पसंदीदा हॉबी या एक्टिविटीज को छोड़ रहे हैं, तो यह एक बड़ा संकेत है।

अपने दोस्तों और परिवार से दूरी बनाना- जब आप अपने पार्टनर के साथ इतना समय बिताते हैं कि आपके पास अपने दोस्तों और परिवार के लिए समय नहीं बचता, तो यह भी एक चिंता का विषय हो सकता है।

अपनी भावनाओं को दबाना- अगर आप हमेशा अपने पार्टनर की भावनाओं को प्रायोरिटी देते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरते हैं, तो यह एक अनहेल्दी रिश्ते का संकेत है।

आप अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं

खुद को बदलने की कोशिश करना- हर व्यक्ति अलग होता है और अपनी आदतें होती हैं। अगर आप अपने पार्टनर के मुताबिक अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह आपके रिश्ते के लिए हानिकारक हो सकता है।

उनकी तुलना दूसरों से करना- अगर आप अपने पार्टनर की तुलना दूसरों से करते हैं, तो यह उन्हें असुरक्षित महसूस करा सकता है और आपके रिश्ते को खराब कर सकता है।

आप हमेशा माफी मांगते हैं

छोटी-छोटी बातों के लिए माफी मांगना- अगर आप हमेशा छोटी-छोटी बातों के लिए माफी मांगते हैं, भले ही आपकी कोई गलती न हो, तो यह एक संकेत है कि आप अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।

आप हमेशा उनके लिए मौजूद रहते हैं

उनके हर फोन कॉल का जवाब देना- अगर आप उनके हर फोन कॉल का तुरंत जवाब देते हैं, भले ही आप बिजी हों, तो यह एक संकेत है कि आप उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं।

आप उनके फैसलों पर सवाल नहीं उठाते

उनके फैसलों से सहमत होना- अगर आप हमेशा उनके फैसलों में हामी भरते हैं, भले ही आप उनसे सहमत न हों, तो यह एक संकेत है कि आप अपनी आवाज दबा रहे हैं।

अगर आप इनमें से कुछ संकेतों को अपने रिश्ते में देख रहे हैं, तो समझ जाएं कि आपके रिश्ते में आप ज्यादा इंवेस्ट कर रहे हैं और अब समय है कि आप इन बातों में कुछ बदलाव करें।

केजरीवाल की घोषणाओं से प्रभावित कई ऑटो वाले भाजपा को छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल

सुषमा रानी

नई दिल्ली, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं से प्रभावित होकर कई ऑटोवाले भाजपा को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी के दिल्ली प्रदेश संगठन मंत्री और ऑटो विंग के प्रभारी गौरव सिंह ने सबको पटका व टोपी पहनाकर ₹आप₹ परिवार में शामिल कराया। इस दौरान ऑटो चालकों के कहा कि अरविंद केजरीवाल की उनके हितों में की गई पांच घोषणाओं से उनमें बेहद उत्साह है। बेटी की शादी में एक लाख रुपए मिलेंगे तो बहुत मदद होगी। साथ ही, इंश्योरेंस होने से अब परिवार की चिंता नहीं रहेगी। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। अभी तक उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं। इसलिए अब हम आम आदमी पार्टी में आ गए हैं और हम मिलकर फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार लाएंगे। वहीं, गौरव सिंह ने कहा कि पूरी दिल्ली के ऑटोवाले मुझे फोन कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद दे रहे हैं। भाजपा से जुड़े कई और ऑटोवाले जल्द आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे।

गौरव सिंह ने कहा कि कुछ ऑटो वाले साथी जो कुछ वक्त पहले भाजपा में चले गए थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं से प्रभावित होकर भाजपा छोड़ दी है और आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। भाजपा के अंदर उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता था। ऑटो वालों ने बताया कि जितना सम्मान उन्हें आम आदमी पार्टी में मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है। उन्हें भाजपा के वादों पर भी कोई यकीन नहीं है। जबकि अरविंद केजरीवाल की गारंटी पक्की गारंटी होती है। वह जो कहते हैं, वो करते हैं। उन्होंने स्कूल, अस्पताल, बिजली और पानी को लेकर जो वादा किया था, उसे पूरा किया। उन्हें यकीन है कि अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों के लिए जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा करेंगे। ऑटोवालों ने कहा कि वह पूरे चुनाव तक तन मन धन अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार करेंगे।

इस दौरान ऑटोवालों ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूलों का मॉडल बदलकर दिखाया है। सरकारी स्कूलों में पहले बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते थे लेकिन अब कुर्सी टेबल पर बैठते हैं और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। मुझे आम आदमी पार्टी का स्कूल मॉडल काफी अच्छा लगा। अरविंद केजरीवाल आने वाले वक्त में दिल्ली में और अच्छा काम करेंगे। आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका सबसे अलग है। अरविंद केजरीवाल किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, वह सभी से मिलते हैं और कार्यकर्ताओं को अपने भाई से ज्यादा मानते हैं। हम अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए थे, उनसे ही जुड़े हुए हैं और हमेशा उनके साथ ही जुड़े रहेंगे।

ऑटोवालों ने कहा कि भाजपा द्वारा हमें धोखा दिया गया। हमने यह देखा कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है और आज हम जीत के साथ खड़े हैं। हम शुरू से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। चाहे शरीर कहीं भी जाए लेकिन आत्मा यहीं रहती है। हमारे क्षेत्र में हमें आम आदमी पार्टी से काफी इज्जत मिलती है, यह इज्जत और कहीं नहीं मिलती है। हम दस साल से अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और भविष्य में भी रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणाएं की हैं, वह हम सब ऑटो वालों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हम उनकी पांच घोषणाओं से काफी प्रभावित हुए हैं। इसलिए हम भाजपा को छोड़कर तुरंत वापस आ गए। देश के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही बेहतर है। पीएम मोदी तो जुमले बाज हैं, उन्हें जुमला करना आता है। आज तक उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया।

केजरीवाल ने ऑटोवालों को दी है ये पांच गारंटी

1- सरकार की तरफ से सभी ऑटोवालों को बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे।

2- साल में दो बार होली और दीपावली पर ऑटोवालों को वर्दी बनवाने के लिए ढाई-ढाई हजार रुपए दिए जाएंगे।

3- हर ऑटोवाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा।

4- ऑटोवालों के बच्चों को किसी भी प्रतिस्पर्धी परीक्षा की कोचिंग करने की फीस सरकार देगी।

5- पूछो एप को दोबारा चालू किया जाएगा। **शिक्षा मंत्री भारत सरकार**

दिल्ली के 16 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अभिभावकों में दहशत

सुषमा रानी

दिल्ली के 16 स्कूलों को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी के बाद नामी स्कूलों में हड़कंप मच गया। धमकी मिलते ही तुरंत स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। पुलिस दमकल बम और डॉग स्कवाड ने मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु स्कूलों के अंदर नहीं मिली।

दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के 16 स्कूलों को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी के बाद नामी स्कूलों में हड़कंप मच गया। धमकी मिलते ही तुरंत स्कूलों की छुट्टी कर दी गई।

पुलिस, दमकल, बम और डॉग स्कवाड ने मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु स्कूलों के अंदर नहीं मिली। पांच दिन पहले नौ दिसंबर को भी 44 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजकर 30 हजार अमेरिकी डालर की फिरौती मांगी गई थी।

पुलिस के मुताबिक पश्चिम विहार के भटनागर इंटरनेशनल स्कूल को सुबह 4.21 बजे, श्री निवासपुरी के कैमब्रिज स्कूल को सुबह 5.50 बजे और डीपीएस अमर कालोनी को सुबह 6.35 बजे धमकी भरी ईमेल मिली। इसी तरह अन्य स्कूलों को भी ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई।

स्कूल प्रबंधन ने ईमेल देखते ही छुट्टी कर दी और संबंधित विभागों को सूचना दी। पुलिस ने बम और डॉग स्कवाड के साथ स्कूलों का कोना-कोना खंगाला। हालांकि किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी संदिग्ध नहीं चीज नहीं मिली। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आपराधिक धमकी और साजिश का मामला दर्ज किया है।

बच्चों को निजी वाहन से स्कूल लेने पहुंचे अभिभावक

धमकी की सूचना मिलते ही अभिभावक निजी वाहन से अपने बच्चों को स्कूल लेने पहुंचे। स्कूलों के बाहर अभिभावकों की कतार लग गई। प्रबंधन ने कतार से बच्चों को बाहर निकाला। इस दौरान कई अभिभावक दहशत में भी नजर आए। कैमब्रिज स्कूल की प्रिंसिपल माधवी गोस्वामी ने बताया कि मैंने सुबह 5:50 बजे मेल चेक किया तो तुरंत पुलिस (Delhi Police) को सूचना दी।

फिर बस चालकों को बताया कि वह किसी भी बच्चे को स्कूल लेकर न आए। अभिभावकों को सूचित किया गया कि शुक्रवार कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। वहीं, आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मामले को अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट डाली है।

उन्होंने लिखा इसी हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी मिली है, जो बेहद गंभीर और चिंताजनक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा? उनकी पढ़ाई का क्या होगा?

इन स्कूलों को मिली धमकी

भटनागर पब्लिक स्कूल पश्चिम विहार, डीपीएस ईस्ट ऑफ कैलाश, डीपीएस आरकेपुरम, कैमब्रिज स्कूल श्रीनिवास पुरी, वेंकटेश पब्लिक स्कूल रोहिणी, ब्रिटिश स्कूल चाणक्यपुरी, मॉडर्न स्कूल, एनडीपीएस स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल, एसडीपी स्कूल डिफेंस कॉलोनी।

रिचमंड ग्लोबल स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल दरियागंज, माउंट कैरमेल स्कूल, डान बास्को स्कूल, एसटीएस स्कूल और डीपीएस वसंत कुंज को धमकी भरा ईमेल भेजा गया।

आप अपने छात्रों के बैग की भी जांच नहीं करते

ईमेल में लिखा है कि यह ईमेल आपको सूचित करने के लिए है कि आपके स्कूल परिसर में कई विस्फोटक हैं और हमें यकीन है कि आप अपने छात्रों के बैग की जांच नहीं करते हैं, जब वे स्कूल में एंट्री करते हैं। एक सीक्रेट डार्क वेब ग्रुप इस गतिविधि में शामिल हैं। बम इतने शक्तिशाली हैं कि वे इमारतों को नष्ट कर सकते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

आज से 14 दिसंबर तक यानी आज और कल दोनों दिन में पैरेंट-टीचर मीटिंग होने वाली है। एक स्कूल अपने स्पोर्ट्स डे के लिए मार्चिंग कर रहा है, जिसमें छात्र इकट्ठा होते हैं। इसलिए 13 और 14 दिसंबर दोनों दिन आपके स्कूल के लिए एक बम विस्फोट का दिन हो सकते हैं।

14 दिसंबर को पैरेंट-टीचर मीटिंग है और यह वास्तव में एक अच्छा मौका है, बम विस्फोट करने का। हमारी मांगें पर विचार करके इस ईमेल का जवाब दें, अन्यथा बम विस्फोट कर दिए जाएंगे।

इस साल राजधानी में बम की धमकी से मिले ईमेल

अगस्त

दिल्ली-एनसीआर में कम से कम 100 अस्पतालों और शापिंग माल को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले।

अस्पतालों में एम्स और सफदरजंग, वसंत कुंज में फोर्टिस, राजेंद्र नगर में सर गंगा राम और द्वारका में मणिपाल अस्पताल शामिल हैं।

मई

दिल्ली-एनसीआर के 150 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की ईमेल मिली।

दिसंबर

दिल्ली के करीब 44 स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज किया

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर, आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, ₹आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन की कोई संभावना नहीं है।"

इससे पहले, दिल्ली में कांग्रेस और AAP के बीच संभावित गठबंधन की अटकलें तेज़ हो गई थीं, विशेषकर तब जब केजरीवाल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। हालांकि, केजरीवाल ने इन अटकलों को निराधार बताते हुए कहा कि AAP आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगी।

पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर स्पष्ट किया कि AAP अकेले चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है।

दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी और किसी भी प्रकार के गठबंधन की योजना नहीं है।

इस प्रकार, दोनों प्रमुख दलों के बीच गठबंधन की संभावनाओं को लेकर चल रही अटकलें अब समाप्त होती दिखाई देती हैं, और दोनों ही पार्टियां आगामी चुनाव में अपने-अपने बलबूते पर मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं।

केजरीवाल की बेबुनियाद बयानबाजी और अमित शाह की निष्क्रियता के कारण ध्वस्त कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों से दिल्ली की जनता त्रस्त है : देवेन्द्र यादव

यादव ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल में महिलाओं के प्रति बिलकुल भी सहानुभूति नही है, उन्होंने बसों में बढ़ती महिलाओं के साथ घटनाओं को बढ़ाने में मार्शलों को पदमुक्त करके सहायता की है जिसके कारण महिलाएं बसों और मेट्रों उत्पीड़न और अत्याचार झेल रही है।

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि अपराध की राजधानी बन चुकी दिल्ली में कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा करने वाली दिल्ली पुलिस मानो ही नही। सरेआम गोलीबारी, लूटपाट, गैंगवार और हत्याएं दिल्ली की दिनचर्या बन चुकी है, आज अगर पड़ोस में हत्या, बलात्कार, लूट या फिर गोलीबारी होती है तो दिल्ली वाले भय के कारण घरों से बाहर नही निकलते है क्योंकि दिल्ली में भाजपा सरकार का दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नही है। राजधानी में बढ़ते अपराधों की जिम्मेदारी लेते हुए अमित शाह तुरंत गृहमंत्री पद से इस्तीफा दें।

उन्होंने कहा कि राजधानी में बदमाश और गैंगवार इस कदर हावी हो रहा है कि दिल्ली का व्यापारी, पेशेवर, महिलाएं और छोटे-बड़े कारोबार करने वाले सहित दिल्ली के छात्र स्कूलों में बम की खबरों से भय के साए में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगातार बढ़ रहे अपराधों को कम करने में पुलिस पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है और अपराधी खुलेआम अपराधों को अंजाम दे रहे है क्योंकि अरविन्द केजरीवाल ने जो स्ट्रीट लाईट और सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया था उसमें दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ स्ट्रीट लाईट और सीसीटीवी कैमरे लगे भी है तो वो बंद पड़े है, पुलिस अपराध रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है, जिसके लिए अरविन्द केजरीवाल और दिल्ली सरकार जिम्मेदार हैं।

यादव ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल में महिलाओं के प्रति बिलकुल भी सहानुभूति नही है, उन्होंने बसों में बढ़ती महिलाओं के साथ घटनाओं को बढ़ाने में मार्शलों को पदमुक्त करके सहायता की है जिसके कारण महिलाएं बसों और मेट्रों उत्पीड़न और अत्याचार झेल रही है।

उन्होंने कहा कि एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का क्राईम ग्राफ लगातार उँचाईयों को छू रहा है। प्रतिदिन 3-4 हत्या, 15 अपहरण जिनमें लगभग 10 महिलाए शामिल है और 5-6 बलात्कार की घटनाएं सहित यौन शोषण, उत्पीड़न की घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है। बुजुर्गों के साथ अपराधों में 11 प्रतिशत की वृद्धि होना चिंता जना है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेता दिल्लीवालों को पूरी तरह बेसहारा छोड़कर दिल्ली के गरीबों के बीच जाकर उनके विकास की बात कर रहे है, उनकी सुरक्षा की गारंटी कोई नही दे रहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अपराधों की बढ़ोत्तरी में सहायक दिल्ली सरकार जो सीसीटीवी, स्ट्रीट लाईट और मार्शल की कमी के लिए जिम्मेदारी है अरविन्द केजरीवाल तुरंत मुख्यमंत्री आतिशी का इस्तीफा लें।

बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए

सुषमा रानी

दिल्ली पुलिस ने एक मुठभेड़ में नीरज बवाना गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। वह हत्या हत्या प्रयास सहित अन्य संगीन वारदातों में शामिल रहा है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कापसहेड़ा बॉर्डर इलाके में विपिन उर्फ काला बंदर को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया था।

दिल्ली। दक्षिण-पूर्वी जिले के एएटीएस स्टाफ ने मुठभेड़ के दौरान नीरज बवाना गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपित घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। वह हत्या, हत्या प्रयास सहित अन्य संगीन वारदातों में शामिल रहा है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कापसहेड़ा बॉर्डर इलाके में विपिन उर्फ काला बंदर को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया था। उसे भी पुलिस की गोली लगी थी।

पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने बताया कि बदमाश की पहचान ग्रेटर कैलाश पार्ट एक के जमरूदपुर निवासी सचिन के रूप में हुई है। पुलिस ने उससे्र अत्याधुनिक पिस्तौल, एक मैगजीन, दो खाली कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। वह लाजपत नगर में हत्या प्रयास के मामले में वांछित था। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि 12 दिसंबर को एएटीएस टीम को सूचना मिली थी कि बदमाश सचिन 13 दिसंबर की सुबह फरीदाबाद से करणी सिंह शूटिंग रेंज रोड होते हुए तुगलकाबाद आएगा।

बदमाश लाजपत नगर फायरिंग की घटना में भी रहा था शामिल

पुलिस को पता चला कि वह अभिषेक उर्फ पिद्दी के साथ लाजपत नगर में हुई फायरिंग की वारदात में भी शामिल रहा है। पुलिस ने करणी सिंह शूटिंग रेंज मुख्य सड़क पर घेराबंदी कर ली। जैसे ही सचिन बाइक से आया तो पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। इस पर आरोपित ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। एक गोली एसआइ शुभम चौधरी की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। जवाबी कार्रवाई में आरोपित सचिन के दाहिने पैर में पुलिस की गोली लगी। तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया और उपचार के लिए एम्स ट्रामा सेंटर भेज दिया।

सुबेग सात वारदातों में रहा है शामिल

मूलरूप से बिहार के मधुबनी के रहने वाला बदमाश सचिन जमरूदपुर में किराए पर रहता है। उसके पिता कैलाश कॉलोनी में रेहड़ी लगाते हैं। 10वीं कक्षा में पढ़ते समय वह अभिषेक उर्फ पिद्दी के संपर्क में आया और उसके साथ काम करने लगा। इसके बाद वह कुख्यात नीरज बवाना गिरोह के बदमाश सुबेग उर्फ शिब्बू के संपर्क में और नाबालिग रहते हुए उसके गिरोह में शामिल हो गया। इससे पहले वह सात वारदात में शामिल रहा है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर पूछताछ में जुट गई है।

गैर -शैक्षिक कर्मचारियों को जल्द परमानेंट करने की रखी मांग

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध अरबिंदो कॉलेज को लंबे अरसे बाद स्थायी प्रिंसिपल मिल गया है। यह पद पर 11 साल बाद स्थायी प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई है। राजधानी कॉलेज में गणित विभाग के प्रोफेसर अरुण चौधरी को प्रिंसिपल बनाया गया है, उन्होंने शुक्रवार को स्थायी प्रिंसिपल पद के रूप में अपना कार्यभार संभाला। इस अवसर पर प्रबंध समिति की चेयरपर्सन प्रो.रूपम कपूर, कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल प्रो.विपिन अग्रवाल ने ज्वाइनिंग के बाद बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कॉलेज की बेहतरी के लिए कार्य करने का कहा। प्रोफेसर चौधरी को बधाई देने वालों का दिनभर तांता लगा रहा। उन्हें बधाई देने वालों में फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस के चेयरमैन डॉ.हंसराज सुमन, विद्वत परिषद सदस्य डॉ.विवेक धनखड़, डॉ. प्रशांत बड़थ्वाल, विनय भारद्वाज, प्रो.विनय सिंह, डॉ.संजय त्यागी, डॉ.ओमप्रकाश, डॉ. राजकुमार वर्मा, डॉ. शिवमंगल कुमार, डॉ.पूनम जैन, प्रो. गिरीश चंद जोशी आदि ने पुष्पगुच्छ भेंटकर व मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दी।

फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन ने प्रो.अरुण चौधरी के अरबिंदो कॉलेज में स्थायी प्रिंसिपल बनने पर उन्हें अंगवस्त्र व पुष्पगुच्छ भेंटकर अपनी बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनसे आग्रह किया है कि जिस तरह से यहाँ पर 100 से अधिक एडहॉक टीचर्स स्थायी हुए हैं ठीक उसी तरह से गैर- शैक्षिक कर्मचारियों के पदों को भी भरा जाए। यहाँ 50 फीसदी कर्मचारी अस्थायी है। उन्होंने बताया है कि इन पदों के विज्ञापन निकाले जा चुके हैं उन्हें भी जल्द से जल्द स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू करें। ये कर्मचारी दस से पंद्रह व उससे अधिक समय से अस्थायी, कंट्रेक्चुअल, टेम्परेरी रूप में कार्यरत है। कुछ कर्मचारी तो उससे अधिक समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया। उन्होंने बताया है कि कॉलेज में लंबे समय से कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति न होने के कारण इनमें बहुत से तो आयुसीमा पार कर चुके हैं, जब भी इनकी सलेक्शन कमेटी या इंटरव्यू हो इन्हें प्राथमिकता देकर स्थायी कराए ताकि लंबे समय से भविष्य व जीवन की अनिश्चितता में जी रहे कर्मचारियों के साथ न्याय सुनिश्चित किया जा सकें।

इस अवसर पर नवनियुक्त प्रिंसिपल प्रो चौधरी ने स्थायी प्रिंसिपल का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात शिक्षकों को अपने संबोधन में कहा कि उनकी प्राथमिकता में छात्र, कर्मचारी व शिक्षकों के हितों का ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार से वित्त पोषित सभी कॉलेजों की बिल्डिंग बन चुकी है लेकिन यह कॉलेज आज भी पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है, सबसे पहले इसकी नई बिल्डिंग जहाँ इसे जमीन मिल चुकी है उस स्थान पर कॉलेज की नई बिल्डिंग बनवाना मेरी प्राथमिकता है, इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन व सरकार से मदद ली जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में स्थायी हुए शिक्षकों की समय पर कन्फर्मेशन लेटर देना व पदोन्नति करना, शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करवाना, इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों के लिए रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम लाना व वंचित समुदायों से आने वाले छात्रों की हर संभव मदद करना मेरी प्राथमिकता में है। उन्होंने आगे कहा कि हम अपने छात्रों को अध्ययन संबंधी किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आने देंगे। छात्रों के बिना शिक्षण संस्थान का कोई अस्तित्व नहीं इसलिए छात्रों की पढ़ाई पर पूरा फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं प्रिंसिपल बाद में हूँ पहले शिक्षक हूँ और एक शिक्षक की तरह मैं भी कक्षा लूंगा।

दारोगा ने वर्दी की हनक दिखाकर धमकाया, फिर थाने से भगाया दो लाख की रिश्वत मामले में सबलू ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

गाजियाबाद के मोदीनगर में एक दारोगा ने गोवंश मांस की तस्करी के मुकदमे से नाम निकालने के एवज में एक युवक से दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी। युवक ने 70 हजार रुपये एडवांस भी दे दिए लेकिन फिर भी उसका नाम मुकदमे से नहीं हटाया गया। परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस उच्चाधिकारियों से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जिले के मोदीनगर में गोवंश के मांस की तस्करी के मुकदमे से नाम निकालने के नाम पर दारोगा ने युवक से दो लाख रुपये रिश्वत मांगी। 70 हजार रुपये एडवांस ले भी लिए। लेकिन नाम नहीं निकाला।

बताया गया कि इस मामले में भोजपुर थाने में वर्ष 2022 में मामला दर्ज हुआ था। नाम नहीं निकलने पर युवक ने अपने रुपये वापस मांगे। लेकिन दारोगा ने धमकाकर भगा दिया। झूठे केस में फंसाने की धमकी दी।

इसके बाद पीड़ति ने पुलिस उच्चाधिकारियों से शिकायत की। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब पीड़ित युवक ने कोर्ट का रास्ता चुना है। कोर्ट के आदेश पर भोजपुर थाने में तैनात दारोगा विपिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीपी मोदीनगर को विवेचना सौंपी गई है।

भोजपुर थाने में दर्ज हुआ था मामला

वहीं, आठ सितंबर 2022 को भोजपुर थाना क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर मांस से भरा मिनी ट्रक हिंदू संगठनों ने पकड़ा था। उनकी शिकायत पर भोजपुर पुलिस ने केस दर्ज किया था। जिसमें मेरठ के फलावदा के सबलू की भी भूमिका दिखाई गई। लेकिन सबलू का आरोप है कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इस प्रकरण से उसका कोई लेना-देना नहीं था। इसके बावजूद भी उनका नाम मुकदमे में जोड़ा गया। विवेचना कर रहे दारोगा विपिन कुमार ने नाम निकालने के नाम पर उनसे दो लाख रुपये की मांग की। सबलू ने उन्हें 70 हजार रुपये दे दिए। रकम दो गवाहों के सामने दी गई।

1.30 लाख के लिए मांगा था समय

बताया गया कि उसने बाकी रकम के लिए कुछ दिन का समय मांगा। लेकिन आरोपित दारोगा ने मुकदमे से नाम नहीं निकाला। शेष 1.30 लाख रुपये लाने का

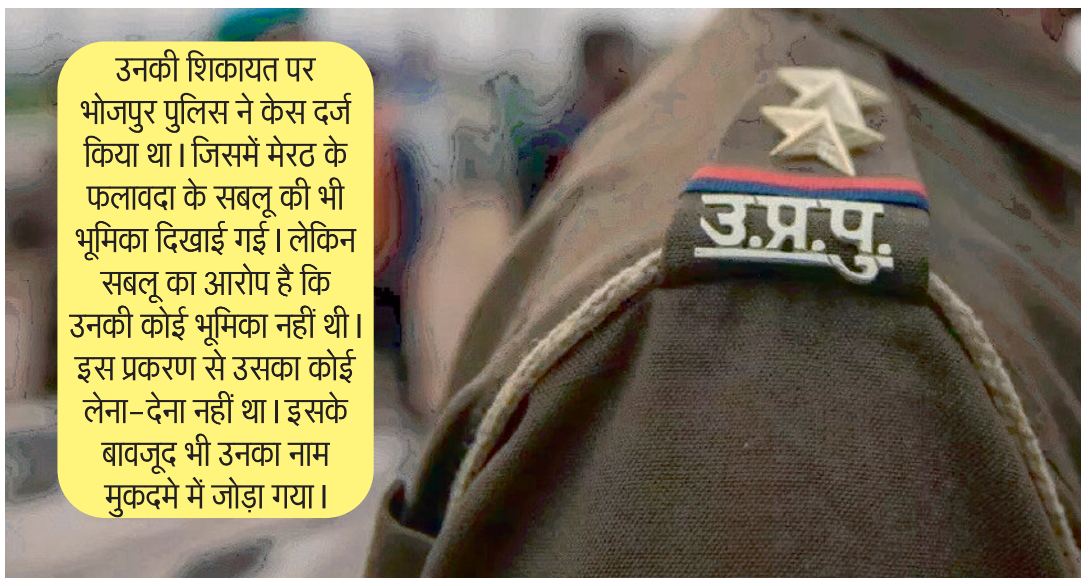

दबाव बनाता रहा। धमकी दी यदि रुपये नहीं दिए तो झूठे मुकदमे में जेल भेज दूंगा। पीड़ित को दारोगा ने वर्दी की हनक दिखाकर दबाव में लिया।

उच्च अधिकारियों से की शिकायत

इसके बाद परेशान होकर सबलू ने पुलिस उच्चाधिकारियों से शिकायत की। लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए उन्होंने कोर्ट में वाद दायर किया। अब कोर्ट ने भोजपुर पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

दारोगा के खिलाफ दर्ज किया गया केस

इस मामले में एसीपी मोदीनगर ज्ञान प्रकाश राय का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर दारोगा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल दारोगा की आगरा में तैनाती है। जांच की जा रही है। उसी आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

बिना एंट्री के सोसायटी में घुसा... कुछ देर घुमा और फिर 14वीं मंजिल से लगा दी छलांग; सुसाइड नोट में बताई वजह

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक शख्स ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान तुषार गोयल के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है लेकिन अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आगे विस्तार से जानिए आखिर पूरा मामला क्या है।

गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन की वीवीआइपी एड्रेस सोसायटी निवासी एक शख्स ने 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं, इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया।

पुलिस को साढ़े 12 बजे मिली सूचना सूचना पर पुलिस मौके पर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, तुषार गोयल नामक व्यक्ति की मौत की सूचना दोपहर साढ़े 12 बजे मिली थी। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

वीवीआईपी एड्रेस सोसायटी का है मामला यह घटना राजनगर एक्सटेंशन की वीवीआईपी एड्रेस सोसायटी की है। बताया गया कि एक युवक शुक्रवार को इस सोसायटी में आया और 14वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। मृतक तुषार गोयल (27 वर्ष) पटेल नगर बी ब्लाक में रहते थे।

बिना एंट्री के सीधे अंदर चले गए पुलिस की जांच में पता चला कि आज सुबह करीब साढ़े 10 बजे वे घर से करीब चार किलोमीटर दूर राजनगर एक्सटेंशन की सोसायटी में आए और बिना एंट्री कराए सीधे सोसायटी के अंदर चले गए।

गार्ड ने एओए को दी सूचना इसके बाद काफी देर तक वे सोसायटी के अंदर ही घूमते रहे। फिर कुछ देर बाद लिफ्ट में चले गए। लिफ्ट के जरिये वह 14वीं मंजिल पर पहुंचे और अचानक से नीचे छलांग लगा दी। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। इसके बाद गार्ड ने मामले की सूचना एओए को दी।

प्रवेश के समय शख्स को नहीं रोका एओए अध्यक्ष यज्ञदत्त त्यागी का कहना है कि सुरक्षागार्ड मुहैया कराने वाली एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

पुलिस को मिला है सुसाइड नोट पुलिस के मुताबिक, मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में उन्होंने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी है।

गाजियाबाद में चला 'अतिक्रमण हटाओ अभियान', दो इलाकों में गरजा प्रशासन का बुलडोजर

परिवहन विशेष न्यूज

नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को साहिबाबाद के वैशाली सेक्टर 4 और कौशांबी में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। इस दौरान लोगों ने हंगामा किया लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद सभी शांत हो गए। वैशाली सेक्टर 4 में अवैध रूप से लगी 30 से अधिक दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद निगम की टीम कौशांबी पहुंची।

साहिबाबाद। नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को कौशांबी और वैशाली सेक्टर चार बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया। इस दौरान लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो सभी शांत हो गए।

वहीं, साहिबाबाद सब्जी मंडी के गेट के बाहर कार्रवाई के एक दिन बाद फिर से ट्रक सड़क पर खड़े हो गए। निगम ने इनको भी हटवा दिया। नगर निगम को शिकायत मिली थी कि वैशाली सेक्टर चार में अवैध रूप से कुछ लोगों ने अस्थायी दुकान लगा ली।

बुलडोजर चलाकर 30 से ज्यादा दुकानों को किया गया ध्वस्त

आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। निगम की टीम शुक्रवार को वैशाली सेक्टर चार पहुंची तो लोग अपनी-अपनी दुकानों को हटाने लगे। कुछ लोग अपना सामान लेकर जाने लगे। बुलडोजर चलाकर 30 से अधिक दुकानों को ध्वस्त कर दिया।

लोगों ने निगम पर ही अस्थायी दुकानों को लगवाने और फिर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया। इसके बाद निगम की टीम कौशांबी पहुंची। कौशांबी मेट्रो स्टेशन के आसपास से सभी ठेली-पटरी वालों को हटा दिया। इस दौरान लोगों ने हंगामा कर दिया। पुलिस और प्रवर्तन दल ने सख्ती दिखाई तो सभी शांत हो गए।

दोबारा अतिक्रमण हुआ तो की जाएगी कार्रवाई

निगम को सूचना मिली कि दो दिन पहले मंडी के बाहर अवैध रूप से खड़े जिन ट्रकों को हटाया था वह फिर खड़े होने लगे हैं। निगम की टीम मौके पर पहुंची। ट्रक चालक को चेतावनी देकर छोड़ दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि निगम की सह पर ही शुक्रवार को ट्रक खड़े हुए थे।

नगर निगम के जोनल प्रभारी सुनील राय ने बताया कि कौशांबी व वैशाली से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। यदि दोबारा अतिक्रमण लगाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रही है। बवाना में करीब सात बीघा कृषि भूमि पर किए गए निर्माण को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया।

निगम का कहना है कि कृषि भूमि पर प्लॉटिंग के इरादे से निर्माण हुआ था। अलीपुर इलाके के बकौली व हिरणकी में भी कृषि भूमि पर अवैध निर्माण गिराए गए। प्रशासन की ओर से की गई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में खलबली मच गई।

होटल में थूक लगाकर रोटी बनाने के मामले में तीन धरे, सीसीटीवी फुटेज देख हर कोई हैरान

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद के मोदीनगर में एक होटल में रोटी बनाते समय एक कारीगर के थूक लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कारीगर आटे की लोई पर थूक रहा है। इस मामले में पुलिस ने होटल मालिक और दो कारीगरों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे विस्तार से पढ़िए आखिर पूरा मामला क्या है।

मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मोदीनगर में कोतवाली क्षेत्र के कृष्णानगर कॉलोनी के निकट स्थित नाज चिकन प्वाइंट में थूक लगाकर रोटी बनाने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। आरोपित तंदूर में रोटी बनाते हुए आटे की लोई पर थूक रहा है। वहीं, होटल में खाना खाने आए युवक की जब नजर पड़ी तो उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल मालिक और दो कारीगरों को पकड़ लिया। तीनों पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। थूक लगाकर रोटी बना रहे आरोपित को पुलिस नाबालिग बता रही है।

रोटी पर बार-बार थूक रहा था आरोपी

कोतवाली क्षेत्र की गोविंदपुरी स्थित डबल स्टोरी कॉलोनी के प्रकाश सिंह अपने दोस्त दीपक के साथ बुधवार की रात को नाज चिकन प्वाइंट पर आए थे। उन्होंने खाना ऑर्डर किया। वे होटल में अंदर बैठे थे। बाहर तंदूर लगा था, जिस पर नाबालिग कारीगर रोटी बना रहा था। आरोपित रोटी बनाते हुए लोई पर बार-बार थूक रहा था।

इस दौरान दीपक की नजर उस पर गई। वह काफी देर तक उसे देखते रहे। इसके बाद होटल मालिक सिखैड़ा हजारी गांव के अनुज को उसकी करतूत बताई, लेकिन होटल मालिक उल्टा उन्हें ही

झूठा बताने लगा।

आरोपी ने दोनों के साथ की गाली-गलौज

इसके बाद आरोपित ने दोनों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। नौबत मारपीट तक पहुंच गई, जिससे प्रकाश और दीपक को चोट आई। प्रकाश ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें रोटी बनाते समय आटे की लोई पर थूकने की पुष्टि हुई।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली। प्रकाश ने भी मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। प्रकाश की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बृहस्पतिवार को वीडियो पूरे दिन सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। लोगों ने कठोर कार्रवाई की मांग की।

एसीपी मोदीनगर ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि आरोपित होटल मालिक अनुज, कारीगर मेरठ के मुंडाली के तालिब व नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। तीनों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

पूर्व में भी सामने आ चुके हैं मामले

ऐसा पहली बार नहीं है कि होटल में थूक लगाकर रोटी बनाने का मामला सामने आया हो। जिले में ऐसे तमाम मामले पिछले सालों में सामने आ चुके हैं। 2021 में भोजपुर के दौसा बंजापुर में शादी समारोह में मामला सामने आया।

इसके अलावा लोनी व मसूरी में भी घटना सामने आई। सभी मामलों में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरोपितों पर कार्रवाई भी हुई। ऐसे मामले में दर्ज मुकदमे की धाराएं जमानती हैं। पुलिस शांतिभंग की धारा में चालान कर देती है।

हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री नीरज शर्मा का कहना है ऐसे मामलों की धाराओं में संशोधन कर कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए।

बदमाशों के लिए काल साबित हो रही यूपी पुलिस, एक साल में गैंगस्टरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

यूपी में गुंडों और बदमाशों की अब खैर नहीं। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने एक साल में अभी तक सात सौ गैंगस्टरों पर कार्रवाई की है। जबकि गैंगस्टर के 50 मामलों में कुल 02 अरब 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति अपने अधीन की। वहीं पर सैंकड़ों अपराधियों पर गुंडा एक्ट लगाया गया।

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने इस साल जरायम (अपराध की दुनिया) की दुनिया में जड़ें जमा चुके बड़े-बड़े अपराधियों पर कार्रवाई की है। एक जनवरी से लेकर अब तक सात सौ गैंगस्टरों पर कराई की है। गैंगस्टर के 50 मामलों में कुल 02 अरब 10 करोड़ 79 लाख 21 हजार 475 रुपये की संपत्ति जब्त की है।

612 अपराधियों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। 198 इनामी बदमाशों में से 156 को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा है। 162 अपराधी जिला बदर किए गए हैं। जिला बदर होने के बावजूद जिले में मिलने पर 40 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं।

एक लाख का इनामी भी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि जिले भर में विभिन्न अपराधों में संलिप्त 198 अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया। उनमें से 156 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। उनमें एक लाख का एक, 25 हजार के 66, 20 हजार के चार, 15 हजार के 20, 10 हजार के 52, पांच हजार के 13 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए।

धूल सरकारी चेहरे पर है, वे आईना साफ कर रहे हैं

(जीतू पटवारी -विनायक फीचर्स)

भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश में भाजपा सरकार के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए दावा किया कि 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों को अब तक 19,212 करोड़ रुपए का अंतरण किया गया। लेकिन, यह अधूरी सच्चाई है सरकार वह तो बता रही है, जो दिया गया, लेकिन यह बताने से बच रही है, जो नहीं दे पाई।

लाडली बहना योजना : वादों और हकीकत का अंतर

मुख्यमंत्री का दावा है लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन सरकार यह स्पष्ट करने में विफल रही कि योजना के तहत 3,000 रुपए प्रतिमाह देने के वादे के बावजूद अब तक बचा हुआ करीब 38,424 करोड़ से ज्यादा रुपया क्यों नहीं दिया गया? यदि यह रकम लाभार्थियों तक पहुंची होती, तो उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार हो सकता था। योजना के लाभार्थियों में से कई महिलाओं ने शिकायत की है कि उन्हें नियमित अंतराल पर भुगतान नहीं मिलता। इसके अलावा, कुछ क्षेत्रों में राशि के वितरण में भेदभाव के आरोप भी लगे हैं। बेहतर होता मुख्यमंत्री ऐसे सभी सवालों का भी जवाब देते।

केन-बेतवा परियोजना : देरी और बढ़ी लागत का जिम्मेदार कौन ?

मध्य प्रदेश की जनता के लिए केन-बेतवा लिंक परियोजना लंबे समय से प्रतीक्षित है। यह परियोजना न केवल प्रदेश में सिंचाई क्षमता बढ़ाने का दावा करती है, बल्कि जल संकट को कम करने का भी वादा करती है। सरकार यह क्यों नहीं बता पा रही है कि शिवराज सिंह चौहान की पूर्ववर्ती सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बीच समन्वय की कमी के कारण इस परियोजना में भारी देरी हुई। अगर इसे समय पर शुरू किया गया होता, तो आज इसकी लागत इतनी न बढ़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 25 दिसंबर को इस परियोजना का भूमि पूजन करते हैं, तो उन्हें इस बजट वृद्धि और देरी के लिए जिम्मेदार कारकों पर भी चर्चा करनी चाहिए।

बीमार स्वास्थ्य सेवा और कितनी बदहाल होगी ?

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय और चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय को एक करने को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया। लेकिन, जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आज भी एंबुलेंस की भारी कमी है। आज भी कई परिवार शवों को कंधे, ठेलागाड़ी और साइकिल पर ले जाने को मजबूर हैं। डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों की कमी के कारण मरीजों को अक्सर बड़े शहरों के अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में प्रति 10,000 जनसंख्या पर डॉक्टरों की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से भी कम है। ग्रामीण अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों की कमी की शिकायतें आम हैं। सरकार द्वारा स्थापित नए मेडिकल कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव और शिक्षकों की कमी भी एक बड़ी समस्या है।

इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन : पुरानी योजना पर श्रेय की नई लड़ाई

इंदौर-मनमाड़ के बीच की रेल लाइन एक ऐसा झुनझुना है, जिसे जो भी मुख्यमंत्री आता है वह अपनी उपलब्धि के रूप में बजाता है। कर्ज लेकर कछुए की गति से चल रही केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार को अब चिंता सिर्फ इस बात की करनी चाहिए कि इस रेल परियोजना को अब बगैर बजट बढ़ाए, तत्काल पूरा किया जाए, ताकि कागजों की घोषणाएं पटरी पर नजर आए।

नदी जोड़ो परियोजना : उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए नदी जोड़ो

परियोजना की कल्पना की थी। लेकिन, भाजपा सरकारों ने इसे भ्रष्टाचार में नहाने का साधन बना दिया। इंदौर से निकलने वाली गंदगी से भरी कान्ह नदी उज्जैन की शिप्रा नदी में मिलकर श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा रही है। इसे सुधारने के नाम पर करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई असर नहीं दिखता। भाजपा के ढेर सारे नेताओं और नौकरशाही की लंबी जमात की कई पीढ़ियों की आर्थिक स्थिति सुधर गई, लेकिन कान्ह नदी की पवित्रता सपना रह गई। सिंहस्थ के नाम पर एक बार फिर नई योजनाओं का प्रस्ताव किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि पुरानी परियोजनाओं के परिणामों का मूल्यांकन करे और उसी के आधार पर नई योजनाएं बनाए।

कृषि-किसान : घोषणाएं ही घोषणाएं

प्रदेश में किसानों की स्थिति में सुधार के सरकार के दावे भी सवालों के घेरे में हैं। सरकार गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर 125 रुपए बोनस देने का ढोल बजा रही है, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में किए गए 2,700 रुपए प्रति क्विंटल के वादे पर चुप्पी साध रही है। महाराष्ट्र में सोयाबीन को 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने का वादा खुद प्रधानमंत्री ने किया गया, जबकि मध्य प्रदेश में केवल 4,892 रुपए प्रति क्विंटल पर सोयाबीन खरीदा गया। धान किसानों को भी सरकार के झूठे वादों का सामना करना पड़ा। 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा के बावजूद किसानों को अपनी फसल औने-पौने दाम पर बेचनी पड़ी।

*** औद्योगिक निवेश और बेरोजगारी***

मध्य प्रदेश सरकार को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि रीजनल इंडस्ट्रियल समिट के नाम पर कागजी निवेश अब पूरे मप्र में ₹पर्यटन₹ कर रहा है। रीजनल इंडस्ट्रियल समिट के नाम पर प्रदेश में निवेश को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन सम्मेलनों के माध्यम से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। लेकिन, सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उद्योगपति, प्रदेश की अस्पष्ट नीतियों और लालफीताशाही के कारण निवेश करने से बच रहे हैं।

उच्च शिक्षा का हाल, बौद्धिक दायरे का पुराना बवाल

डॉ. मोहन यादव ने उच्च शिक्षा में अपने कार्यकाल को उपलब्धि बताते हुए कहा कि उन्होंने ₹कुलपति₹ को ₹कुलगुरु₹ कर दिया। लेकिन यह बदलाव केवल शब्दों का खेल है। चिंता का एक बौद्धिक दायरा यह भी है कि पुरानी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर चुके डॉक्टर मोहन यादव विश्वविद्यालयों की राजनीति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कांग्रेस जानना चाहती है कि क्या इससे शिक्षा में सुधार हो गया? मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने की घोषणा से क्या उच्च शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में बदलाव हुआ? जमीनी हकीकत यह है कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज केवल कागजों में ही दौड़ रहे हैं, क्योंकि आज भी पुरानी समस्याओं के ऊपर नई योजना के नामकरण का कागज कोई भी आसानी से पढ़ और समझ सकता है। छात्रों और शिक्षकों की संख्या में असंतुलन, अव्यवस्थित पाठ्यक्रम और बुनियादी ढांचे की कमी शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख समस्याएं हैं।

कर्ज-क्राइम की "करप्शन इंडस्ट्री"

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दावा किया कि मोहन यादव सरकार तुरंत एक्शन लेकर काम कर रही है। सकारात्मक और सार्थक विपक्ष के रूप में हम जनता की तरफ से यह जानना चाहते हैं कि यह तुरंत एक्शन मप्र से क्राइम, करप्शन और कमीशन के कल्चर को कम क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों सबसे ज्यादा अपराध मध्य प्रदेश में तब हो रहा है, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ही प्रदेश के गृहमंत्री हैं? क्यों तबादला उद्योग के नाम पर सरकार ने देर रात तक चलने वाली "करप्शन इंडस्ट्री" खोल रखी है? क्यों कोई भी योजना अब बगैर कमिशन तय किए कागजों में दर्ज नहीं हो पाती है?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा सरकार का एक साल कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। जनता अब केवल वादों और दावों से संतुष्ट नहीं है। उसे वास्तविक परिणाम चाहिए। अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ भी मुखरता से यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि कर्ज में डूबे प्रदेश के संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे किया जाएगा? अंधेरनगरी के मुखिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'मौन' तो तोड़ा, लेकिन, न पुरानी डफली को छोड़ा, न कोई नया राग जोड़ा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि धूल सरकारी चेहरे पर है और वे आईना साफ कर रहे हैं। कर्ज, क्राइम और करप्शन सरकार के मुखिया अपने कार्यकाल को बेमिसाल कह रहे हैं। *(लेखक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं।)

- :सौजन्य :-
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

इलेक्ट्रिक वाहन विकास को गति देंगे: ग्रीन भारत शिखर सम्मेलन में नितिन गडकरी ने कहा

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार, 13 दिसम्बर को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग पांच साल में दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग बन जाएगा और इस विकास यात्रा में इलेक्ट्रिक वाहनों को सबसे बड़ा चालक माना जाएगा।

नई दिल्ली के ताज पैलेस मे नेटवर्क 18 ग्रीन भारत शिखर सम्मेलन में नितिन गडकरी जी ने कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार 7 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जब उन्होंने मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था।

गडकरी जी ने कहा, ₹आज उद्योग का आकार 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है और हम जापान को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटो उद्योग बन गए हैं। अमेरिका इस सूची में सबसे ऊपर है, जिसका उद्योग आकार 78 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, उसके बाद चीन 47 लाख करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि 5 साल में हम दुनिया में पहले स्थान पर होंगे और ई-वाहन उद्योग के विकास को आगे बढ़ाने वाला प्राथमिक कारक होगा।₹

उन्होंने दावा किया कि भारत के पास पर्याप्त जनशक्ति, कच्चा माल और अन्य सभी कारक हैं जो भारत को लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए आवश्यक हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव आर्थिक रूप से व्यवहार्य होगा। इससे भारत को निर्यात और व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का बाजार आकार लगभग 22 लाख करोड़ रुपये का है। चीन 47 लाख करोड़ रुपये के साथ सबसे आगे है, उसके बाद अमेरिका 78 लाख करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है।

रोसेनबॉयर ने डलास लव फील्ड एयरपोर्ट पर लाया पैंथर 6x6 इलेक्ट्रिक

परिवहन विशेष न्यूज

रोसेनबॉयर अमेरिका और डलास फायर रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने एक अभिनव साझेदारी की है जिसका उद्देश्य PANTHER 6x6 इलेक्ट्रिक के संयुक्त विकास से लेकर श्रृंखला उत्पादन तक है। प्री-सीरीज़ वाहन 2025 के मध्य में वितरित किया जाएगा और डलास लव फील्ड एयरपोर्ट पर संचालित होगा, जिससे यह PANTHER 6x6 इलेक्ट्रिक प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन जाएगा।

डलास फायर-रेस्क्यू डिपार्टमेंट एक सहयोगी भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग 6 महीने के परीक्षण चरण के दौरान, वाहन को उसके चरणों से गुजरना होगा। परीक्षणों में दैनिक संचालन में एकीकरण, वर्तमान बेड़े की तुलना में प्रदर्शन और प्रशिक्षण संचालन में कार्यक्षमता शामिल होगी। प्राप्त अंतर्दृष्टि उत्पाद टीम को दी जाती है और सीधे आगे के विकास में प्रवाहित होती है। परीक्षण चरण के पूरा होने के बाद, पैंथर 6x6 इलेक्ट्रिक को नियमित परिचालन वाहन के रूप में बेड़े में एकीकृत किया जाएगा।

अंतरिम अग्निशमन प्रमुख जस्टिन बॉल ने कहा, ₹डलास अग्निशमन बचाव विभाग, रोसेनबॉयर के साथ एक नई और टिकाऊ प्रौद्योगिकी के निर्माण और विकास में साझेदारी करने के अवसर पर गर्व और उत्साहित है, जो हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगा और साथ ही हमारे निवासियों और हर साल डलास लव फील्ड से गुजरने वाले लाखों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।₹

रोसेनबाउर इंटरनेशनल के सीईओ सेबेस्टियन वुल्फ कहते हैं, ₹पैंथर 6x6 इलेक्ट्रिक के साथ, हम हवाई अड्डे के

अग्निशमन वाहनों के क्षेत्र में प्रदर्शन और उत्सर्जन में कमी के मामले में एक नया मानक स्थापित कर रहे हैं। हमें डलास फायर-रेस्क्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस नई तकनीक का परीक्षण और उपयोग करने पर गर्व है।₹

डलास फायर-रेस्क्यू डिपार्टमेंट डलास शहर के लिए अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए जिम्मेदार है और इसलिए, डलास लव फील्ड एयरपोर्ट पर अग्निशमन वाहनों के बेड़े की देखरेख भी करता है, जहाँ DAL ARFF स्टेशन 21 पर PANTHER 6x6 इलेक्ट्रिक का उपयोग किया जाएगा। डलास शहर का विमानन विभाग स्थिरता पर विशेष ध्यान देता है और 2040 तक उत्सर्जन-मुक्त होने की योजना बनाता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मौजूदा फायर स्टेशन को ₹DAL ARFF स्टेशन 21 प्रतिस्थापन₹ परियोजना के हिस्से के रूप में फिर से डिज़ाइन और पुनर्निर्माण किया जा रहा है। डलास लव फील्ड में नया फायर स्टेशन न केवल आधुनिक होगा और प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए इष्टतम स्थिति में होगा, बल्कि ऊर्जा दक्षता और स्थिरता की ओर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इसमें बेड़े के वाहनों को धीरे-धीरे वैकल्पिक ड्राइव सिस्टम वाले वाहनों से बदलना भी शामिल है।

रोसेनबाउर इंटरनेशनल के मुख्य बिक्री अधिकारी एंड्रियास ज़ेलर ने कहा, ₹पैंथर 6x6 इलेक्ट्रिक को आगे बढ़ाने के लिए हम डलास फायर रेस्क्यू डिपार्टमेंट और डलास लव फील्ड के साथ साझेदार के रूप में सहयोग करने के लिए उत्साहित हैं। डलास लव फील्ड में वास्तविक परिचालन स्थितियों से प्राप्त निष्कर्षों को वाहन के अनुकूलन में शामिल किया जाएगा। इससे भविष्य में हवाई अड्डों के लिए कम उत्सर्जन वाले वाहनों का उपयोग करके अपने कार्बन पदचिह्न को और कम करने का मार्ग प्रशस्त होगा।"

19 दिसंबर को पेश होगी Kia Syros SUV, इन 8 फीचर्स से हो सकती है लैस

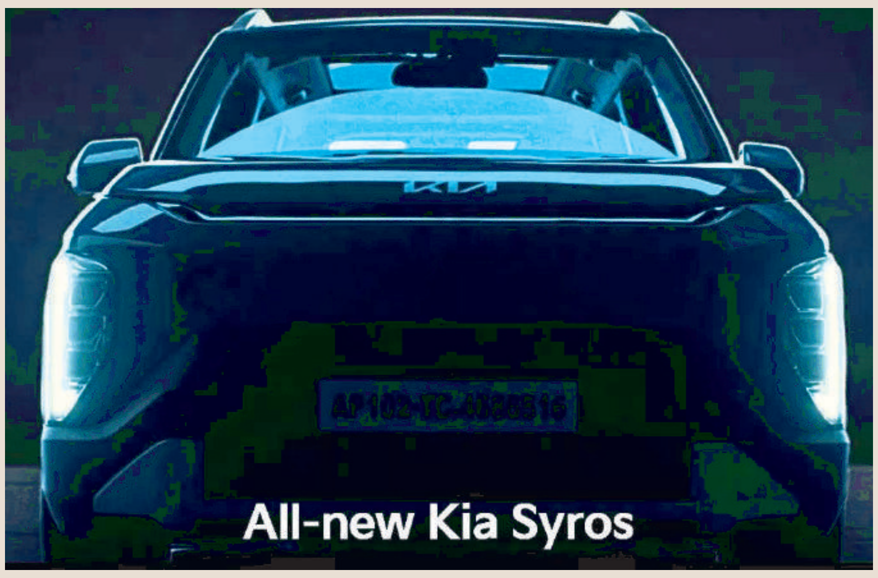

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय बाजार में 19 दिसंबर को पेश होगी। भारत में पेश होने से पहले कंपनी कई बार टीजर के जरिए इसके कुछ फीचर्स को दिखा चुकी है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको ऐसे 7 फीचर्स के बारे में बता रहे हैं जो किआ साइरोस में देखने के लिए मिल सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

नई दिल्ली। भारत में 19 दिसंबर को पेश होने जा रही है। इसे भारत में पेश करने से पहले कई बार किआ इंडिया टीज कर चुकी है। हालांकि, अभी तक इसके फीचर्स और पावरट्रेन की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इसकी स्पाई फोटो से पता चलता है कि इसमें कई फीचर्स देखने के लिए मिल सकता है। आइए जानते हैं कि यह Kia Syros किन फीचर्स के साथ भारत में एंट्री मार सकती है।

1. फ्यूचरिस्टिक डिजाइन

साइरोस का डिजाइन फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। यह भारतीय बाजार में बिकने वाली दूसरी कारों से काफी अलग दिखने वाली है। वहीं, साइरोस की डिजाइन के साथ कन्वेंशन शब्द काफी कुछ कहता है। वहीं, इसके पहिए भी ज्योमैट्रिक पैटर्न के हैं।

2. एक्टीरियर

Kia Syros SUV में वर्टिकल एलईडी हेडलाइट्स, हाई-माउंटेड एलईडी टेल लाइट सिग्नेचर, बम्पर-माउंटेड ब्रेक लाइट्स, 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, फ्लश डोर हैंडल, कम से कम एक रिक्वेस्ट सेंसर के साथ कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं।

3. इंटीरियर

साइरोस में एक नया इंटीरियर डिजाइन थीम देखने के लिए मिल सकता है, जो भारत में किसी दूसरी किआ कार में अभी तक नहीं देखा गया होगा। इसें ऑफसेट लोगो के साथ नया स्टीयरिंग व्हील हो सकता है। साथ ही इंफोटेनमेंट स्क्रीन में वॉल्यूम के लिए रोलर्स के साथ-साथ फिजिकल कंट्रोल भी देखने के लिए मिल सकते हैं।

4. इंटीरियर फीचर्स

Kia Syros SUV में ट्विन 10.2-इंच डिस्प्ले देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन एंड्रॉइड ऑटो और ऐपल कारप्ले को वायरलेस सपोर्ट के साथ मिल सकते हैं। इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड, ऑटो-डिमिंग IRVM, कूल्ड ग्लोव बॉक्स, प्रीमियम बोस साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग समेत और भी फीचर्स देखा जा सकता है।

5. पैसेंजर कंफर्ट

किआ साइरोस का सिल्हूट बॉक्सी होने वाल है, जिसकी वजह से यह सोनेट से ज्यादा स्पेस के साथ आ सकती है। इसका टॉलबॉय डिज़ाइन की वजह से इसमें ज्यादा हेडरूम और बूट स्पेस मिस सकता है। इसमें वेंटिलेटेड सीट के साथ ही ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का भी फीचर मिलेगा।

6. रियर वेंटिलेटेड सीटें

Kia Syros SUV की रियर सीटें रिक्लाइनिंग फीचर्स के साथ आएगी, जो बैक भी हो सकती है और पीछे की विंडो शेड मौजूद होंगे। इसमें रियर-वेंटिलेटेड सीटें भी मिल सकती हैं। इसके पीछे वाली सीटों में वायरलेस चार्जिंग पैड भी देखने के लिए मिल सकता है।

7. सेफ्टी फीचर्स

किआ साइरोस में लेवल-2 ADAS का फीचर देखने के लिए मिल सकता है। जिसकी वजह से यह सोनेट में मिलने वाले फीचर्स से एक कदम आगे निकल जाएगी। इसमें साइड और कर्टेन एयरबैग, 3-पॉइंट सीट बेल्ट, लोड लिमिटर और प्री-टेंशनर, सीट बेल्ट रिमाइंडर समेत और भी सेफ्टी फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं।

ग्रीव्स रिटेल ने बाउमा कॉनएक्सपो इंडिया 2024 में लांच किये नए इलेक्ट्रिक निर्माण उपकरण लॉन्च किए

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड के एक प्रभाग, ग्रीव्स रिटेल ने बाउमा कॉनएक्सपो इंडिया 2024 में इलेक्ट्रिक लाइट कंस्ट्रक्शन उपकरणों की अपनी नई रेंज का अनावरण किया। कंपनी टिकाऊ, शून्य-उत्सर्जन समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती है जो परिचालन लागत को कम करते हुए प्रदर्शन को बढ़ाती है।

नए लॉन्च किए गए उत्पादों में भारी-भरकम उत्खनन कार्यों के लिए डिज़ाइन की गई मिनी एक्सकेवेटर रेंज शामिल है। ये एक्सकेवेटर 2-टन से 4-टन श्रेणी में उपलब्ध हैं और इनमें एक शक्तिशाली कुबोटा इंजन है जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन देता है।

ग्रीव्स रिटेल ने 6 मीटर से लेकर 14 मीटर तक की प्लेटफ़ॉर्म ऊँचाई वाली इलेक्ट्रिक सिज़र लिफ्ट पेश की है, जो इसे इनडोर और आउटडोर दोनों तरह के प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त बनाती है। यह लिफ्ट उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें ओवरलोड सेंसिंग और स्वचालित ब्रेकिंग शामिल है, जो सुरक्षित और कुशल संचालन सुनिश्चित करती है। इसका बैटरी से चलने वाला संचालन शून्य-उत्सर्जन और शांत प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।

इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक बूम लिफ्ट 13.8 मीटर की प्लेटफ़ॉर्म ऊंचाई और 7.81 मीटर की क्षैतिज पहुंच प्रदान करती है, जो इसे शहरी और सीमित स्थानों के लिए उपयुक्त बनाती है। यह मशीन या तो जीरो-मेंटेनेंस लीड एसिड या लिथियम बैटरी के साथ उपलब्ध है, जिससे रखरखाव की आवश्यकता कम होती है।

ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड की सहायक कंपनी एक्सेल कंट्रोलिंकेज प्राइवेट लिमिटेड ने इस कार्यक्रम में अपनी उन्नत इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में उच्च प्रदर्शन वाले गियर शिफ्ट लीवर, केबल और वाणिज्यिक वाहनों और निर्माण उपकरणों के लिए घटक शामिल थे। प्रदर्शनी में मांग वाले वातावरण में स्थायित्व और दक्षता के लिए डिज़ाइन किए गए धातु से बने रबर उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए।

ग्रीव्स रिटेल के सीईओ नरसिंह जयकुमार ने कहा, ₹भारत में निर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सरकारी निवेश के कारण विस्तार कर रहा है। विद्युतीकृत निर्माण उपकरणों की हमारी नई रेंज स्थिरता को बढ़ावा देते हुए इस वृद्धि का समर्थन करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

निर्माण उपकरण क्षेत्र में ग्रीव्स रिटेल का प्रवेश इसकी विविधीकरण रणनीति का हिस्सा है, जो विभिन्न उद्योगों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपने बहु-उत्पाद और बहु-ईंधन पेशकशों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है।

दिसंबर 2024 में ह्युंडई की गाड़ियों पर बंपर डिस्काउंट, 85 हजार रुपये तक की मिल रही छूट

2024 हुंडई अपनी गाड़ियों पर दिसंबर 2024 में बंपर डिस्काउंट दे रही है। इस छूट में नकद छूट एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट छूट को शामिल किया गया है। हुंडई की एक्सटर वेन्यू वर्ना और टक्सन जैसे चुनिंदा मॉडल पर साल के अंत में छूट दिया जा रहा है। साल के अंत में हुंडई अपनी गाड़ियों पर 85 हजार रुपये तक का डिस्काउंट दे रही हैं।

नई दिल्ली। साल के आखिरी महीने में हुंडई अपनी गाड़ियों पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। दिसंबर 2024 के लिए हुंडई ने अपनी गाड़ियों पर डिस्काउंट ऑफर कर रही ह। इस डिस्काउंट में नकद छूट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट छूट शामिल हैं, जो एक्सटर, वेन्यू, वर्ना और टक्सन जैसे चुनिंदा मॉडल पर मिल रहा है। आइए जानते हैं कि हुंडई की गाड़ियों पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है।

Hyundai Grand i10 Nios

हुंडई ग्रैंड i10 निओस कुल 68,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जो इसके पेट्रोल-मैनुअल वेरिएंट पर मिल रहा है।

इसके बेस स्पेक एरा और CNG वेरिएंट पर 25,000 तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है।

इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट पर 30,000 रुपये की नकद छूट दी जा रही है।

इसपर एक्सचेंज बोनस 20,000 रुपये तो कॉर्पोरेट डिस्काउंट 3,000 रुपये दिया जा रहा है।

Hyundai Grand i10 Nios की एक्स-शोरूम कीमत 5.92 लाख रुपये से लेकर 8.56 लाख रुपये तक है।

Hyundai i20

हीरो ने भारत में बंद की अपनी तीन मोटरसाइकिल, अब नहीं मिलेंगी ये बाइक्स

परिवहन विशेष न्यूज

हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी तीन बाइक को भारत में बंद कर दी है। इसमें हीरो एक्सट्रीम 200S 4V हीरो XPulse 200T और Passion XTEC शामिल है। इसमें से एक्सट्रीम 200S 4V और हीरो XPulse 200T मोटरसाइकिल 200cc की है और वहीं Passion XTEC एक कंप्यूटर बाइक है। आइए जानते हैं कि यह तीनों बाइक किन फीचर्स के साथ आती थी।

नई दिल्ली। हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में अपने लाइनअप से तीन मॉडल को बंद कर दिया हैं, इसके साथ ही कंपनी ने अपनी वेबसाइट से भी हटा दिया है। ये मोटरसाइकिलों की लिस्ट में Hero Xpulse 200T 4V, Xtreme 200S 4V और Passion Xtec शामिल है। आइए जानते हैं कि जब यह भारत में मिलती थी तो यह किन फीचर्स के साथ आती थी।

Hero Xpulse 200T 4V

हीरो एक्सपल्स 200T 4V एक स्ट्रीट बाइक है जो एक्सपल्स 200 4V पर बेस्ड है। वहीं, यह एक ऑफ-रोड बाइक है। इसमें 199.5cc सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड, फोर-वॉल्व इंजन ऑफर किया जाता था, जो 19.1 PS की पावर और 17.35 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

इस नेकेट टूरर बाइक में आगे की तरफ LED DRLs के साथ एक गोल LED हेडलैंप, एक LED टेल लैंप और एक फुल-LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया था। इसमें इंस्ट्रूमेंट कंसोल में स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और रियल-टाइम राइडिंग डेटा डिस्प्ले दिया गया था, जिसमें इनकमिंग कॉल और एसएमएस अलर्ट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती थी।

Xtreme 200S 4V

यह एक फुल-फेयर्ड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल थी। इसमें 199.6 cc का इंजन मिलता था, जो 18.08 PS की पावर और 16.15 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। इसमें क्लिप-ऑन हैंडलबार और पीछे की तरफ सेट फुटपेग थे, जो मोटरसाइकिल को स्पोर्टी और आरामदायक राइडिंग पोस्चर भी दिया गया था। इसमें फुल-फेयर्ड डिज़ाइन और स्लीप एलईडी हेडलैंप ने मोटरसाइकिल को स्पोर्टी अपील देती थी। बाइक में 17-इंच के पहिए दिए गए थे, जिसमें डायमंड-टाइप फ्रेम, टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ मोनोशॉक था।

Hero Passion Xtec

यह पैशन पर बेस्ड एक कम्प्यूटर मोटरसाइकिल थी। इसे पैशन एक्सटेक ड्रम ब्रेक और पैशन एक्सटेक डिस्क ब्रेक दो वेरिएंट में लाया गया था। इसमें 113.2cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन दिया गया था, जो 9.15 PS की पावर और 9.79 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। इसके इंजन को 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया था।

इसमें कॉल और एसएमएस के लिए अलर्ट देने के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया था। इसमें फोन की बैटरी प्रतिशत, रियल-टाइम माइलेज, लो-फ्यूल इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ इंडिकेटर जैसी जानकारी मिलती थी। इसके अलावा बाइक में एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया था।

भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता

विभिन्न शैक्षिक सुधारों और नीतियों के बावजूद, भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली को बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में महत्त्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले शैक्षणिक पथ और सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल के बीच की खाई के कारण चुनौतियों का सामना कर रही है। कई सुधारों के बावजूद, इन मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए आमूलचूल परिवर्तन की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता बनी हुई है। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को वास्तविक दुनिया की मांगों के अनुरूप कौशल प्रदान करना, जीवन के मील के पत्थर और आधुनिक चुनौतियों के लिए तत्परता बढ़ाना है।

-प्रियंका सौरभ

कोठारी आयोग ने स्कूली शिक्षा में एकरूपता की नींव रखी और शैक्षिक सुधारों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इसने 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफ़ारिश की, जिसने भारत की शिक्षा प्रणाली में भविष्य के सुधारों के लिए मंच तैयार किया। इस नीति ने शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका उद्देश्य समानता में सुधार करना और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। इसने पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम पेश किया और व्यावहारिक कौशल विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर ज़ोर दिया। इस योजना का उद्देश्य पोषण मानकों में सुधार करना और स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना था। एसएसए का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना और लैंगिक और सामाजिक असमानताओं को ख़त्म करना था। आरटीई अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया, जिससे सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित हुई। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य सीखने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर शिक्षा को वास्तविक दुनिया की ज़रूरतों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाना था। इसने रटने की आदत से हटकर परियोजना-आधारित सीखने और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित किया।

समग्र शिक्षा अभियान एकीकृत योजना का उद्देश्य समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार करना था। इसने हाशिए पर पड़े छात्रों के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और समावेशी शिक्षा के लिए स्कूलों को अनुदान प्रदान किया। एनईपी 2020 ने प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कक्षा 10 के बाद कठोर धाराओं को ख़त्म करने जैसे परिवर्तनकारी बदलावों का प्रस्ताव रखा। यह समग्र विकास के उद्देश्य से शिक्षा के मार्गों में बहु-विषयक सीखने और लचीलेपन पर ज़ोर देता है। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली बहुआयामी चुनौतियाँ क्षेत्रों में गुणवत्ता की असमानताएँ हैं। भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में एक महत्त्वपूर्ण अंतर है, जहाँ कई ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढाँचे और योग्य शिक्षकों की कमी है। एएसईआर 2018 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 50% बच्चे ही बुनियादी पाठ पढ़ सकते हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता में असमानताओं को उजागर करता है। शिक्षा प्रणाली अक्सर सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती है, जिससे छात्र कार्यबल में आवश्यक व्यावहारिक नौकरी कौशल के लिए तैयार नहीं होते हैं।

इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में डिग्री वाले स्नातकों में अक्सर नौकरी-विशिष्ट कौशल की कमी होती है, जिससे उच्च बेरोजगारी दर होती है। प्रणाली अभी भी रटने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करती है, जिससे सीमित आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान क्षमताएँ होती हैं। आईसीएसई और सीबीएसई में, परीक्षाएँ अनुप्रयोग-आधारित सीखने के बजाय सामग्री को याद करने पर केंद्रित होती हैं, जिससे रचनात्मक सोच में बाधा आती है। शिक्षक प्रशिक्षण की कमियाँ: शिक्षकों के प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण अंतर है, जो शिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। शिक्षकों की कमी और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण को पर्याप्त रूप से सम्बोधित करने में विफल रहने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की आलोचना की गई है। डिजिटल शिक्षा के विकास के बावजूद, तकनीकी बुनियादी ढाँचा अपर्याप्त बना हुआ है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने प्रगति की है, लेकिन ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट की पहुँच और डिवाइस की पहुँच अभी भी कम है, जिससे छात्रों का आधुनिक शैक्षिक उपकरणों से संपर्क सीमित हो जाता है।

भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता वास्तविक दुनिया के कौशल के साथ संरेखण की मांग करती है। आमूलचूल परिवर्तन छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के बजाय व्यावहारिक कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, शिक्षा को वास्तविक दुनिया की मांगों के साथ संरेखित कर सकता है। फ़िनलैंड की शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक कौशल और हाथों से सीखने पर ज़ोर देती है, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों की अधिक सहभागिता और रोज़गार क्षमता होती है। आमूलचूल सुधार लचीले शिक्षा मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जिससे छात्रों को उनकी रुचियों के आधार पर अलग-अलग सीखने के मार्ग अपनाने की अनुमति मिलती है। जर्मनी की दोहरी शिक्षा प्रणाली व्यावसायिक शिक्षा और अकादमिक शिक्षा के बीच संतुलन प्रदान करती है, जिससे रोज़गार क्षमता में सुधार होता है। अधिक छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण में बदलाव से छात्रों में रचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और आलोचनात्मक तर्क को बढ़ावा मिलेगा। इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) कार्यक्रम रचनात्मकता, संस्कृति और संज्ञानात्मक कौशल सहित छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।

आमूलचूल परिवर्तन उच्च-दांव वाली परीक्षाओं से दूर जा सकता है और अधिक निरंतर मूल्यांकन विधियों को अपना सकता है, जिससे छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम हो सकता है। सिंगापुर ने छात्रों के प्रदर्शन को मापने, तनाव को कम करने और सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निरंतर मूल्यांकन रणनीतियों को लागू किया है। आमूलचूल परिवर्तन से पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा को शामिल किया जा सकता है, जिससे पहुँच और सहभागिता बढ़ सकती है। कौशल-आधारित शिक्षा को शामिल करने जैसे पारंपरिक सुधारों से परे अभिनव समाधान। शुरुआती चरण में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल-आधारित शिक्षा शुरू करने से छात्रों को व्यावहारिक क्षमताओं से लैस किया जाएगा, जिससे वे कार्यबल के लिए तैयार होंगे। दक्षिण कोरिया तकनीकी शिक्षा को मिडिल स्कूल से अपने पाठ्यक्रम में एकीकृत करता है, जिससे एक कुशल कार्यबल तैयार होता है। ऑफ़लाइन और ऑनलाइन सीखने का संयोजन शैक्षिक विभाजन को पाट सकता है, जिससे जुड़ाव और पहुँच बढ़ सकती है। स्कूलों में मिश्रित शिक्षा दूरदराज के क्षेत्रों में छात्रों को आमने-सामने बातचीत से लाभान्वित करते हुए डिजिटल सामग्री तक पहुँचने की अनुमति देती है। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग स्कूलों के लिए बुनियादी ढाँचे, प्रशिक्षण और संसाधनों को बढ़ा सकता है, विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में। ब्रिटिश काउंसिल भारतीय राज्यों के साथ मिलकर शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार और वैश्विक शिक्षण मानकों को पेश करती है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर शिक्षण परिणाम मिलेंगे। उदाहरण के लिए: जापान ने अपने पाठ्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को एकीकृत किया है, जिससे छात्रों के कल्याण और प्रदर्शन में सुधार हुआ है। स्थानीयकृत शिक्षा मॉडल: क्षेत्रीय आवश्यकताओं और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप शिक्षा प्रणालियों को तैयार करने से जुड़ाव और प्रासंगिकता में सुधार होगा।

भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए आमूलचूल सुधारों की आवश्यकता है। फिनलैंड के छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण और दक्षिण कोरिया के व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरणा लेते हुए, भारत भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के लिए NEP 2020 के दृष्टिकोण के साथ मिलकर समावेशी और टिकाऊ शैक्षिक परिणाम प्राप्त कर सकता है।

भारत को एक स्वास्थ्य सेवा, एक शिक्षा की आवश्यकता है

विजय गर्ग

"एक स्वास्थ्य सेवा, एक शिक्षा" भारत में एकीकृत और न्यायसंगत प्रणाली की एक महत्वपूर्ण मांग है। यह क्यों महत्वपूर्ण है इसका विवरण यहां दिया गया है:

एक हेल्थकेयर

समान पहुँच: एक मानकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध हों, चाहे उनका स्थान या सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

* असमानताओं में कमी: यह शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच अंतर को पाट देगा, जिससे आबादी के समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होगा।

* कुशल संसाधन आवंटन: एक एकीकृत प्रणाली संसाधनों के बेहतर आवंटन, बर्बादी को रोकने और यह सुनिश्चित करने की अनुमति देगी कि धन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।

* मानकीकृत गुणवत्ता: एक एकल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली चिकित्सा शिक्षा, लाइसेंसिंग और अभ्यास के लिए समान मानक स्थापित करेगी, जिससे देखभाल की बेहतर गुणवत्ता होगी।

एक शिक्षा

* गुणवत्ता आश्वासन: एक एकीकृत शिक्षा प्रणाली देश भर में शिक्षा के एक निश्चित मानक की गारंटी देगी, यह सुनिश्चित करेगी कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण सीखने का अनुभव प्राप्त हो।

* क्षेत्रीय असमानताओं में कमी: यह राज्यों और क्षेत्रों के बीच शैक्षिक विभाजन को पाटने में मदद करेगा, जिससे सभी छात्रों को समान अवसर मिलेंगे।

* सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम: एक मानकीकृत पाठ्यक्रम छात्रों के लिए राज्यों के भीतर और राज्यों में स्कूलों और कॉलेजों के बीच संक्रमण को आसान बना देगा।

* कौशल विकास: एक एकीकृत प्रणाली कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण, छात्रों को नौकरी बाजार के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।

कार्यान्वयन चुनौतियाँ

हालाँकि "एक स्वास्थ्य सेवा, एक शिक्षा" का विचार आकर्षक है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं:

* विविधता: भारत विभिन्न सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों वाला एक विविध देश है। एक आकार-सभी के लिए फिट दृष्टिकोण सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है।

* राज्य स्वायत्तता: राज्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, जिससे एक समान प्रणाली लागू करना मुश्किल हो जाता है।

* संसाधन आवंटन: राज्यों और क्षेत्रों में संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी।

* बुनियादी ढांचा: ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

जबकि "एक स्वास्थ्य देखभाल, एक शिक्षा" का लक्ष्य प्रशंसनीय है, व्यावहारिक चुनौतियों पर विचार करना और एक व्यावहारिक दृष्टिकोण तैयार करना आवश्यक है जो क्षेत्रीय आवश्यकताओं के साथ राष्ट्रीय मानकों को संतुलित करता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने और एक मजबूत, स्वस्थ और अधिक शिक्षित भारत के निर्माण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास महत्वपूर्ण है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट

कहीं आपको तो नहीं सोशल मीडिया - रील्स देखने का एडिक्शन

विजय गर्ग

रामी को जैसे ही घर के कामों से फुर्सत मिली, उसने अपना मोबाइल उठाया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर रील्स देखना शुरू कर दिया। रील्स देखते-देखते कब एक घंटा गुजर गया, उसे पता ही नहीं चला। उसने सोचा था, बस दो चार रोल्स देखकर फिर अपने जरूरी काम करेगी। लेकिन एक घंटे से ज्यादा समय रोल्स देखते-देखते निकल गया। ईशानी को बहुत बुरा लगा कि उसने अपना इतना समय रील्स देखकर खराब कर दिया। लेकिन फिर शाम के वक्त थोड़ा खाली समय मिलने पर वह दोबारा रील्स देखने में मशगूल हो गई। वैसे इस तरह की समस्या से दो चार होने वाली सिर्फ हो नहीं है। आजकल हर दूसरा व्यक्ति सोशल मीडिया और रोल्स देखने के एडिक्शन के जाल में फँस गया है। आखिर क्या है, सोशल मीडिया और रील्स का एडिक्शन ? इसका शिकार होने पर किस तरह की समस्याएं लोगों के जीवन में आती है ? इससे कैसे बचा जा सकता है ? हमें जरूर जानना चाहिए।

क्या है सोशल मीडिया रील्स का एडिक्शन

आज दुनिया पूरी तरह से हाईटेक हो चुकी है। फोन के जरिए ही हम अपने बहुत से काम घर बैठे-बैठे कर लेते हैं। जैसे शॉपिंग करना, विल्स भरना। ऐसे जरूरी और समय लेने वाले काम आसानी से फोन के जरिए हो जाते हैं, जिससे लोगों के पास बहुत सारा समय बचता है। ऐसे में इस बचे हुए समय में वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो जाते हैं। शुरुआत में थोड़ा ही समय इन प्लेटफॉर्म पर लोग बिताते हैं, लेकिन वक्त के साथ उन्हें सोशल मीडिया कंटेंट और रोल्स देखने का चस्का सा लग जाता है। रोल्स देखते-देखते, वे भूल जाते हैं कि अपना कितना समय बर्बाद कर चुके हैं। घर हो या ऑफिस, जरा सा खाली समय मिलते ही लोग रोल्स देखने में बिजी हो जाते हैं। धीरे-धीरे यह आदत कब एडिक्शन में बदल जाती है, लोगों को पता भी नहीं चलता है। क्या कहती है स्टडी पिछले साल सामने आई एक स्टडी के अनुसार छह में से एक भारतीय हर रोज लगभग डेढ़ घंटा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुजारता है, इसमें भी अधिक समय वह रोल्स देखने में गुजार देता है। सोचने और चिंता करने वाली बात है कि सिर्फ रील्स देखने में ही हर रोज एक घंटे से अधिक का समय लोग सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं और इसके बदले में कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी उनको नहीं मिलता है।

ऐसे करें एडिक्शन को कंट्रोल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और रील्स का एडिक्शन अगर किसी को भी है तो ऐसा नहीं है कि वह इससे छुटकारा नहीं पा सकता है। इससे छुटकारा पाना या सोशल मीडिया एडिक्शन को बहुत हद तक कंट्रोल करना मुमकिन है। बस लोगों को थोड़ा जागरूक होना होगा। उन्हें खुद के समय की और जिंदगी की अहमियत को समझना होगा। साथ ही कुछ छोटी-छोटी बातों को महत्व भी देना होगा, जिससे वे सोशल मीडिया कंटेंट और रील्स के एडिक्शन से बाहर आ सकें। जैसे आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना ही है, रील्स देखनी ही है तो टाइम लिमिट सेट करके देखें। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाँच टाइम को आप फिक्स कर सकती हैं। तय किए गए समय के बाद आपके सामने मैसेज आता है. कि आप आगे रील्स देखना चाहते हैं या नहीं ? इस मैसेज के आने पर आपको तुरंत ही फोन बंद कर देना चाहिए। आपको रील्स कुछ घंटों के लिए देखनी भी है तो नॉलेज देने

वाली रील्स देखें। रील्स या कंटेंट ऐसा हो, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम करें। वरना बेकार कंटेंट से दूरी ही बनाकर रखें।

हॉबीज को अहमियत दीजिए

सोशल मीडिया पर एक्टिव ना रहने पर आप शुरुआती दौर में बोरियत महसूस कर सकती हैं। लेकिन इस बोरियत को दूर करने के लिए आप क्रिएटिव कामों में खुद को बिजी रखना सीखें। इसके लिए बुक रीडिंग की आदत डालें, इससे आपकी नॉलेज और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ेगी। इसके अलावा आप गार्डनिंग, पेंटिंग जैसी हॉबीज भी अपनाएं। साथ ही अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के संग क्वालिटी टाइम बिताएं, उनसे अपने मन की बातें साझा करें। उनके साथ खुशी भरे पल बिताएं। इन सभी बातों को फॉलो करके आप रोल्स या सोशल मीडिया एडिक्शन से बच पाएंगी और अपने बचे हुए कीमती समय में कुछ बेहतर और अच्छा काम कर पाएंगी

x एक्सपर्ट की राय लें

अगर आप रील्स या सोशल मीडिया पर बहुत टाइम बिता रही है और इसे कंट्रोल करने में नाकामयाब हो रही है तो आखिर में उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फोन से डिलीट हो कर दें। अगर आपका रील्स और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का एडिक्शन अधिक बढ़ गया है और आप उसे कंट्रोल करने में असफल हो रही हैं तो एक्सपर्ट की राय लें। वह आपको इस एडिक्शन से बाहर आने में मदद करेंगे।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

सेवा बनाम मेवा

सम्मान अच्छे कार्यों की स्वीकृति होकर व्यक्ति की प्रशंसा का परिचायक है। अच्छी उपलब्धि और हितकारी कार्य करनेवाले के कार्य का एक सकारात्मक मूल्यांकन होता है। अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने या विशिष्ट कार्य करने पर सभी प्रकार की संबंधित संस्थाएं, संगठन या प्रकल्प उपलब्धि प्राप्तकर्ता का व्यक्तिगत या उससे जुड़े समूह का सम्मान - अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हम आए दिन देखते हैं। सार्वजनिक या सामाजिक रूप से यह सम्मान दोनों ओर के वातावरण में एक प्रकार से उत्साह का संचार करता है। सम्मान देने वाला जितना महत्वपूर्ण कार्य करता है, उससे अधिक सम्मान प्राप्त करने वाले का उत्साहवर्धन होता है। उसने जो कार्य किया है, सम्मान देने वालों की उसके प्रति निष्ठा और सकारात्मक दृष्टिकोण प्रकट होता है जो अन्य के लिए भी प्रेरक होता है। उनमें भी अपने कार्य के प्रति लगन और उत्साह पैदा करता है। सम्मान, दोनों पक्षों में आत्मविश्वास बढ़ाता है, इसलिए सम्मान करना हमारे यहां की संस्कृति और परंपरा है।

सामाजिक हित, राष्ट्रहित, विशेष क्षेत्र या विशेष सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्य, प्राप्त की गई उपलब्धि या किए गए त्याग, जो समाज, देश और उस क्षेत्र को गौरव प्रदान करे, मानव जाति का भला करे, मार्गदर्शन करे, अन्य के लिए आदर्श और प्रेरक बने ऐसे व्यक्तित्व को चुनकर संस्था, संगठन, समाज, देश स्तर से लेकर विश्व स्तर तक सम्मान की परंपरा है और विशेष अवसरों पर सार्वजनिक रूप से सम्मान के लिए सम्मान समारोहों का आयोजन किया जाता है। समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ व्यक्ति मौन रहकर कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो उचित होता है, वैसा करते हैं, करते जाते हैं, वे किसी को बताते नहीं। अपने कार्य के अतिरिक्त समय में से समय निकाल कर भला कर सकने योग्य होते हैं। भले लोग भला करने में लग जाते हैं तो कुछ जीवनपर्यंत भले कार्य को अपना लेते हैं। जो ऐसे लोगों और उनके कार्य व्यक्तित्व की परख करते हैं, वे उन्हें प्रकाश में लाते हैं। मीडिया के माध्यम से या अन्य सम्मान करने योग्य संस्था को बताकर उनके महत्व को प्रकट करते हैं, सम्मान प्रदान करने के माध्यम से। मगर इसमें अगर किसी कोण से स्वार्थ घुसता है तो व्यक्ति के चुनाव पर असर पड़ता है और फिर इसके बाद सम्मान की गरिमा भी प्रभावित होती है, क्योंकि जिस आम जनता को कई बार मासूम और निरपेक्ष समझ लिया जाता है, उसकी नजर सधी हुई होती है।

कुछ व्यक्ति या संस्थाएं मेवा के लिए सेवा करते हैं, ताकि अधिसंख्य लोग उनकी सेवा को ध्यान में रखकर उसको जानें-पहचानें और राजनीति में पद प्राप्ति का अवसर आने पर सेवा कार्य को भुनाकर पद प्राप्त कर सकें और सेवा का स्थायी पारिश्रमिक प्राप्त कर सकें। ऐसे में दूसरे भी उनकी सिफारिश कर सकें कि ये समाज सेवक हैं। ऐसे व्यक्ति सेवा के माध्यम से अपना निवेश करते हैं और अवसर आते ही कई गुना ज्यादा भुनाने की व्यवस्था कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति या ऐसी संस्थाएं लोकप्रियता के मामले में उच्च दर्जे पर बने रहते हैं। इस श्रेणी में अधिकांश स्वयंसेवी संगठन और सेवा के बदले लाभ का पद प्राप्त करने वाले लोग आते हैं। उनके कानों में इस तरह की लोकोक्तियां गूंजती रहती हैं, 'करेंगे सेवा तो मिलेगा मेवा।' उनके लिए यह जरूरी भी होता है कि वे बताएं कि सेवा के क्षेत्र में उन्होंने किया क्या है! या फिर यों ही वित्त पोषण प्राप्त करते रहते हैं और अपने लोगों या खुद को सम्मान दिलवाते रहते हैं। कुछ लोग लोकप्रियता की चर्चा या सुर्खियों में बने रहने के लिए भी सेवा कार्य करते हैं। उन्हें उसी में मजा आता है। यह उनकी जिजीविषा होती है और उनके लिए इतना ही पर्याप्त होता है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि सम्मान मानव समाज की गरिमा को बढ़ाते हैं। सच्चे और भले लोगों का सम्मान मानवीयता और इंसानियत का सम्मान है। बुद्धिजीवी और सहृदय लोग और समाजों की यही पहचान है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा को समाज याद रखता है। हां, अगर सेवा के बदले मेवा प्राप्त करने की इच्छा हो या फिर शर्त हो तो उसे सेवा नहीं माना जाता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने वालों को भी कभी-कभी शंका की दृष्टि से देखने लगे जाते हैं और उन पर अंगुली उठाने लग जाते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ वैसे लोग जिम्मेदार होते हैं, जो स्वार्थ के मकसद से सेवा करने का ढोंग करते हैं। ऐसे में यह बहुत जरूरी होता है कि पूरी बात जान ली जाए, उसकी तह तक जाया जाए, परखा जाए और तब उसके बाद धारणाएं बनाई जाएं। अनुचित धारणा बनाने से मानवीय भावना कुंद होती है, उसे हानि पहुंचती है।

इन सबसे हटकर सुलक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुपथ पर चलकर अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति, जो अपनी और सबकी गरिमा बढ़ाए, जो समाज में उत्साह जागृत कर प्रेरणा प्रदान करे, सम्माननीय होता है। दबंगई और ताकत के बल पर सम्मान पाना अलग बात है और विनय के भाव में रह कर और दूसरों का निस्वार्थ भाव से भला कर, उपलब्धि प्राप्त कर सम्मान पाना अलग बात है। सम्मान, उत्साह, ऊर्जा, गरिमा और सकारात्मकता का प्रेरक होता है। इसलिए सम्मान की परंपराओं से विरत नहीं हुआ जा सकता। इससे अच्छी बात भला क्या होगी कि भले और अच्छे लोगों का सम्मान होता रहे, निस्वार्थ और सच्चे लोगों का सम्मान होता रहे।

विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल शैक्षिक स्तंभकार स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर

भूख और कुपोषण से जूझते लोग

दुनिया की आबादी के साथ भूख की समस्या भी बढ़ रही है। ऐसे कई राष्ट्र हैं, जो इस समस्या से बुरी तरह जूझ रहे हैं। मानवता के लिए भुखमरी एक गंभीर समस्या है, न केवल जीवन को प्रभावित करती, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता को भी जन्म देती है। यह विडंबना ही है कि तकनीकी और आर्थिक प्रगति के बावजूद इक्कीसवीं सदी में भी वैश्विक भुखमरी बड़ी चुनौती बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार दुनिया भर में बयासी करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी के शिकार हैं। विश्वभर में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जिन्हें दो समय का भोजन नसीब नहीं होता। पोषण पाषण युक्त और पर्याप्त भोजन न मिल पाने के कारण दुनिया की बड़ी आबादी कुपोषण की चपेट में है। भोजन को बुनियादी और मौलिक मानवाधिकार माना गया है, लेकिन पूरी दुनिया में खाद्यान्न की कमी और कुपोषण के कारण प्रतिवर्ष लाखों लोग जान गंवा देते हैं। भोजन, हवा और पानी के बाद तीसरा सबसे बुनियादी अधिकार हर किसी को पर्याप्त भोजन है। जबकि दुनिया भर के किसान वैश्विक आबादी से ज्यादा लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन बनी रहती है। दुनिया से भुखमरी मिटाने के प्रयासों में जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय तनाव और आर्थिक समस्याएं सबसे बड़ी बाधा बन रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, बार-बार मौसम में होने वाले बदलावों, संघर्षों, आर्थिक मंदी, असमानता और महामारी कारण विश्व में करीब 73 करोड़ 30 लाख लोग भूख का सामना कर रहे हैं, जिसका सर्वाधिक असर गरीब तबके पर पड़ता है, जिनमें से कई कृषक परिवार हैं। कोरोना काल के बाद लंबे समय से चल रहे रूस-यूक्रेन और इजराइल-फिलिस्तीन युद्ध जैसी विकट परिस्थितियां भी भूख की समस्या को और विकराल बना रही हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना कि भूख और कुपोषण लंबे समय तक चलने वाले संकटों से और बढ़ जाते हैं।

आज दुनिया में करोड़ों लोग स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। 'एफएओ' के मुताबिक विश्व में २.8 अरब से ज्यादा लोग स्वस्थ आहार का खर्च उठाने में असमर्थ हैं और अस्वास्थ्यकर आहार ही सभी प्रकार के कुपोषण का प्रमुख कारण है। कमजोर लोगों को प्राय: मुख्य खाद्य पदार्थों या कम महंगे खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहने के लिए विवश होना पड़ता है, जो अस्वास्थ्यकर हो सकते हैं, जबकि अन्य लोग ताजे या विविध खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता से पीड़ित हैं। उन्हें स्वस्थ आहार चुनने के लिए जरूरी जानकारी की कमी है या फिर वे केवल सुविधा लिए विकल्प चुनते हैं। । दुनिया भर में प्रतिवर्ष हर दस में से एक व्यक्ति दूषित भोजन के कारण बीमार हो जाता है और हर साल 4.२ लाख लोगों की मौत का कारण दूषित भोजन ही है, जिनमें करीब सवा लाख बच्चे भी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 'खाद्य एवं कृषि संगठन' के अनुसार २०२१ दुनिया भर में पांच लाख लोगों की मौत भूख से हुई। थी। हालांकि पृथ्वी पर इतना अनाज पैदा हो रहा, जिससे दुनिया के हर व्यक्ति को पर्याप्त भोजन मिल सके, पर सबसे बड़ी समस्या सभी तक पोषणयुक्त आहार और उपलब्धता है।

भुखमरी मानवता की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली गंभीर वैश्विक चुनौती है, जिसे समाप्त करने के लिए स्थायी नीतियों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र का २०३० तक सतत विकास लक्ष्य भुखमरी को समाप्त करने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है, जिसके तहत सभी के लिए पोषणयुक्त, सुरक्षित और पर्याप्त भोजन सुनिश्चित । करने पर जोर दिया गया है। यदि समुचित प्रयास किए जाएं तो २०३० तक भुखमरी मुक्त दुनिया का सपना साकार हो सकता है। बहरहाल, भुखमरी केवल भोजन की कमी नहीं, एक सामाजिक और नैतिक संकट है, जिसे समाप्त करना केवल सरकारों का कर्तव्य नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। एक संगठित प्रयास के माध्यम से हम सभी मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं, जहां कोई भी भूखा न सोए।

2025 में कैसा रहेगा स्टॉक मार्केट का रुख, बाजार के सामने क्या होंगी चुनौतियां ?

परिवहन विशेष न्यूज

साल 2024 अब खत्म होने वाला है और कुछ हफ्तों में नया साल यानी 2025 का आगाज होगा। वर्ष 2024 में शेयर बाजार में शानदार उछाल के साथ भारी गिरावट भी आई। इस गिरावट के कारण निवेशकों को नुकसान का सामना करना पड़ा। अब निवेशकों की नजर आगामी साल पर बनी हुई है। जानते हैं कि साल 2025 में शेयर बाजार की मुख्य चुनौतियां क्या हैं?

नई दिल्ली। साल 2024 अपने अंत पर आ गया है और जल्द ही वर्ष 2025 का आगाज होगा। वर्ष 2024 की बात करें तो इस साल शेयर बाजार ने रिकॉर्ड बनाएं हैं, हालांकि, बाजार में भारी गिरावट आई। इस गिरावट से निवेशकों को लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान भी हुआ है। अब निवेशकों की नजर अगले साल यानी वर्ष 2025 पर बनी हुई है।

हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि 2025 में शेयर बाजार के कारोबार को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं।

साल 2024 में कैसा रहा कारोबार

कोरोना महामारी के कारण साल 2020 में भारी गिरावट आई थी। इस साल शेयर बाजार ने इस गिरावट को रिकवर कर लिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के बेंचमार्क निफ्टी 2020 के निचले स्तर से तीन गुना ज्यादा उछल गया है। इस साल हुए लोक सभा चुनाव के नतीजे आने से एक दिन पहले स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ रैली दिखी, लेकिन नतीजे आने के बाद बाजार में भारी बिकवाली आ गई।

भारत के स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन की बात करें तो वह लॉन्ग टर्म हिस्टॉरिकल एवरेज से ज्यादा है। 2024 के अंत में शेयर बाजार में बहुत अनिश्चितता देखने को मिल रही है। विदेशी निवेशकों द्वारा जारी आउटफ्लो के कारण बाजार निचले स्तर को छू गया। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस अनिश्चितता के कारण 2025 में शेयर बाजार के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी होंगी।

शेयर बाजार के लिए क्या रहेंगी चुनौती ?

भू-राजनीतिक चिंता का असर वैश्विक बाजार पर देखने को मिलता है। वर्ष 2024 में भी यूक्रेन-रूस युद्ध और इजरायल-ईरान के बीच चल रहे विवाद के कारण निवेशकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अमेरिकी बाजार की चाल और राजनीति का असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आई। डॉलर और रुपये के एक्सचेंज में रुपये की वैल्यू कम हो गई।

अमेरिकी शेयर बाजार की बात करें तो इस बाजार का पूंजीकरण सही है। एसएंडपी 500 अपने ट्रेलिंग अर्निंग से लगभग 28 गुना की उछाल पर है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर घोषणा किया है। इस घोषणा के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में निकासी शुरू किया, जिसके कारण स्टॉक मार्केट अपने निचले स्तर से भी गिर गया।

2025 में ये रहेंगी मुख्य चुनौतियां

ट्रंप को मात दे सकती है इकोनॉमी

वर्ष 2025 में ग्लोबल इकोनॉमी और मार्केट में उतार-चढ़ाव का प्रमुख फैक्टर ट्रंप हो सकता है। माना जा रहा है कि ट्रंप कई कठोर फैसले लेंगे। इन फैसलों का असर शेयर बाजार पर सीधा पड़ेगा। हालांकि, ट्रंप ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जो इकोनॉमी के लिहाज से तर्कसंगत या सही न हो।

ट्रंप ने चीन से होने वाले इम्पोर्ट पर 60 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अमेरिका में चीन में बने सामान का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और 30 प्रतिशत टैरिफ लगाने से भी इन वस्तुओं के दाम बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। इससे फेड रिजर्व की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी जो अमेरिका की इकोनॉमी में महंगाई कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इंटरेस्ट रेट में कटौती के साइकिल को रोकने, जिसे शुरू करने में फेड को सफलता मिली है, का दुनियाभर की इकोनॉमी पर सामान्य रूप से और अमेरिकी की इकोनॉमी पर खास तौर पर बुरा असर देखने को मिलेगा।

डॉ. वी के विजयकुमार, मुख्य निवेश रणनीतिकार (चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट), जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज

डॉलर का मजबूत होना

अमेरिकी चुनावों के बाद डॉलर मजबूत हुआ है। अगर अमेरिका में कॉरपोरेट टैक्स 15 फीसदी हो जाता है तो इससे कंपनियों की कमाई बढ़ जाएगी। इसका लाभ अमेरिकी बाजार में दिखेगा क्योंकि अधिक पूंजी का निवेश होगा। इसके अलावा डॉलर और मजबूत होगा।

2025 में डॉलर और मजबूत होता है तो यह उभरते बाजारों के लिए चुनौती बनेगा। हालांकि, डॉलर ज्यादा समय तक मजबूत नहीं रहेगा क्योंकि अमेरिकी निर्यात (एक्सपोर्ट) को बढ़ावा देने के लिए ट्रंप कमजोर डॉलर चाहते हैं।

ग्रोथ की रफ्तार में कमी

भारत की सबसे बड़ी चिंता इकोनॉमिक ग्रोथ की सुस्त रफ्तार है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी 5.4 फीसदी रही। अब सवाल आता है कि यह नरमी केवल एक तिमाही के लिए था या फिर स्लोडाउन स्ट्रक्चरल है। अगर स्लोडाउन स्ट्रक्चरल है तो इसका असर शेयर बाजार पर नेगेटिव पड़ेगा। उम्मीद है कि फिस्कल और मौद्रिक प्रोत्साहन (मॉनेटरी स्टिमुलस) के कारण तीसरी और चौथी तिमाही में भारत की इकोनॉमी ग्रोथ में तेजी आएगी।

भारत की ग्रोथ स्टोरी होगी शानदार

लॉन्ग टर्म में देखें तो भारत की जीडीपी ग्रोथ काफी बेहतर नजर आ रही हैं। डॉ. वी के विजयकुमार, मुख्य निवेश रणनीतिकार (चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट), जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुसार भारत की स्थिर राजनीतिक प्रणाली, डेमोग्राफिक डिविडेंड, समाज के उद्यमशील होने, डिजिटल क्षेत्र में लीडरशिप और तेजी से बढ़ते स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के दम पर आने वाले कई वर्षों तक भारत में तेज आर्थिक वृद्धि बनी रहने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय इकोनॉमी और मार्केट लचीला बना रहेगा।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टैक्स लगाएगा आस्ट्रेलिया, मेटा-गूगल को भी देना पड़ेगा कर

आस्ट्रेलिया सरकार ने कहा कि वह अब बड़े डिजिटल प्लेटफार्म और सर्च इंजनों पर टैक्स लगाएगी। अगर ऐसा होता है कई बड़ी कंपनियां जैसे मेटा (Meta) गूगल (Google) अल्फाबेट (Alphabet) और बाइटडांस (ByteDance) भी आस्ट्रेलिया सरकार को टैक्स देगी। अभी तक सरकार ने यह नहीं बताया है कि वह इन कंपनियों से कितना टैक्स लेगी। आइए इस आर्टिकल में पूरी बात जानते हैं।

एपी, मेलबर्न। आस्ट्रेलिया की सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह समाचार के लिए भुगतान नहीं करने वाले बड़े डिजिटल प्लेटफार्म और सर्च इंजनों पर टैक्स लगाएगी। इन पर तब तक टैक्स लगाया जाएगा, जब तक वे आस्ट्रेलियाई समाचार मीडिया संगठनों के साथ राजस्व साझा करने के लिए सहमत नहीं होते।

सहायक वित्त मंत्री स्टीफन जोंस और संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने बताया कि एक जनवरी से उन कंपनियों पर टैक्स लगाया जाएगा, जो आस्ट्रेलिया में सालाना 1.60 करोड़ डालर से अधिक का राजस्व अर्जित करती हैं। इनमें मेटा (Meta), गूगल (Google), अल्फाबेट (Alphabet) और बाइटडांस (ByteDance) जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

आस्ट्रेलियाई मीडिया संगठनों को दिए जाने वाले धन की इस टैक्स से भरपाई होगी। हालांकि यह नहीं बताया गया कि कितना टैक्स लगाया जाएगा। जोंस ने पत्रकारों से कहा, 'इस कदम का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना नहीं है।' फेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram) और वाट्सएप (WhatsApp) के स्वामित्व वाली कंपनी मेटा ने आस्ट्रेलियाई समाचार प्रकाशकों को उनकी सामग्री के लिए भुगतान करने के तीन वर्ष के समझौते को नवीनीकृत नहीं करने की घोषणा की है।

ठंड में लेट हो गई ट्रेन ! अब टिकट कैंसिल करने पर क्या मिलेगा पूरा रिफंड?

परिवहन विशेष न्यूज

ठंड में कई ट्रेनें लेट से चलती है। इसका असर भारतीय रेलवे के संचालन के साथ यात्रियों को भी पड़ता है। ट्रेन लेट होने के कारण कई यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर घंटो इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में कई यात्रियों के मन में सवाल रहता है कि ट्रेन लेट होने के कारण टिकट कैंसिल कर दी जाए तो क्या उन्हें फुल रिफंड मिलेगा?

नई दिल्ली। भारत के उत्तरी राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। इसमें कोहरे का असर आम लोगों के साथ ट्रेन के संचालन पर पड़ता है। ठंड में जब घने कोहरा होता है तो इसकी वजह से कई ट्रेनें लेट चलती है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट हो जाती हैं या फिर कैंसिल हो जाती है।

ट्रेन के कैंसिल होने पर तो यात्रियों को टिकट की पूरी राशि मिल जाती है। लेकिन, ट्रेन के लेट होने पर भी क्या रिफंड मिलता है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों को पूरा रिफंड पाने का अधिकार दिया है। हालांकि, इसके लिए कुछ नियम व शर्तें अवश्य होती हैं। हम आपको इस आर्टिकल में इसके बारे में बताएंगे।

कब मिलता है पूरा रिफंड ?

भारतीय रेलवे के नियमों (Indian Railway Rule) के अनुसार अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट होती है तो यात्री को टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। हालांकि. अगर यात्री ने तत्काल टिकट बुक किया है तब टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

फुल रिफंड पाने के लिए यात्रियों को टिकट डिपॉजिट रसीद सबमिट करनी होगी।

कहां फाइल करें टीडीआर

यात्री आईआरसीटीसी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर टीडीआर फाइल कर सकते हैं। ऑफलाइन टीडीआर फाइल करने के लिए उन्हें टिकट काउंटर पर जाना होगा। टिकट काउंटर पर जाकर उन्हें टिकट सरेंडर करना होगा, जिसके बाद उन्हें पूरा रिफंड मिल जाएगा। आपको बता दें कि टीडीआर या टिकट सरेंडर करने के बाद रिफंड मिलने में न्यूनतम 90 दिन लगते हैं।

कैसे फाइल करें टीडीआर

सबसे पहले IRCTC के वेबसाइट पर यूजरआईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।

अब 'Services' के ऑप्शन में जाकर "File Ticket Deposit Receipt (TDR)" को सेलेक्ट करें।

इसके बाद My Transactions पर क्लिक करें।

अब स्क्रीन पर "File TDR" ऑप्शन शो होगा, उसे सेलेक्ट करें।

अब सभी जानकारी देने के बाद सबमिट करें।

इसके बाद क्लेम रिक्वेस्ट भारतीय रेलवे को भेजा जाएगा। रेलवे द्वारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद आपको रिफंड मिल जाएगा।

नोट कर लें कि रिफंड की राशि उस बैंक अकाउंट में आएगी जिसके जरिये आपने टिकट बुक की थी।

अब विदेश से जमकर आएगा पैसा! RBI ने प्रवासी भारतीयों की विदेशी मुद्रा जमा पर बढ़ाई ब्याज दर

परिवहन विशेष न्यूज

आरबीआई ने बैंकों को अब एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष से कम अवधि की एफसीएनआर (बी) जमाएं अल्पकालिक वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) जमा चार प्रतिशत दर पर जुटाने की अनुमति दे दी है जबकि पहले यह 2.50 प्रतिशत थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि भारत के पास अपने व्यापार को डी-डॉलराइजकरने की कोई योजना नहीं है।

नई दिल्ली। आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों की विदेशी मुद्रा जमाओं पर ब्याज दर सीमा बढ़ाने का एलान किया है। इस कदम का उद्देश्य रुपये पर दबाव के बीच पूंजी प्रवाह को बढ़ाना है। केंद्रीय बैंक ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है।

शुक्रवार से बैंकों को अब एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष से कम अवधि की एफसीएनआर (बी) जमाएं अल्पकालिक वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) जमा चार प्रतिशत दर पर जुटाने की अनुमति दे दी है, जबकि पहले यह 2.50 प्रतिशत थी।

इसी तरह, तीन से पांच वर्ष की अवधि की परिपक्वता अवधि वाली जमाओं पर एआरआर प्लस पांच प्रतिशत ब्याज दिया जा सकता है, जबकि पहले यह सीमा 3.50 प्रतिशत थी। एफसीएनआर पर यह छूट अगले वर्ष 31 मार्च तक ही उपलब्ध रहेगी।

'म्यूलहंटर एआई' से बैंकों की जुड़ने की सलाह

आरबीआई ने शुक्रवार को बैंकों से कहा कि वे उसकी पहल 'म्यूलहंटर डाट एआइ' के साथ सहयोग करें, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूल खातों (फर्जी खातों) को हटाया जा सके। म्यूल खाता एक बैंक खाता है, जिसका इस्तेमाल अपराधी अवैध तरीके से पैसा लूटने के लिए करते हैं।

आरबीआई ने शुक्रवार को बैंकों से कहा कि वे उसकी पहल 'म्यूलहंटर डाट एआइ' के साथ सहयोग करें, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूल खातों (फर्जी खातों) को हटाया जा सके। म्यूल खाता एक बैंक खाता है, जिसका इस्तेमाल अपराधी अवैध तरीके से पैसा लूटने के लिए करते हैं।

गुमनाम व्यक्ति इन खातों को खोलकर इसमें लोगों से ठगी के पैसे जमा कराते हैं। इन खातों से धन हस्तांतरण का पता लगाना और उसे वापस पाना मुश्किल होता है।

डी-डॉलरीकरण की योजना नहीं: दास

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि भारत के पास अपने व्यापार को 'डी-डॉलराइज' (de-dollarization) करने की कोई योजना नहीं है। इसका मतलब है कि भारत दूसरे साथ के साथ व्यापार में डॉलर का इस्तेमाल घटाने की दिशा में नहीं बढ़ रहा है।

आरबीआई गवर्नर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने का विकल्प चुनते हैं तो उन पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा ब्रिक्स मुद्रा के बारे में दास ने कहा कि यह समूह के सदस्यों द्वारा दिया गया एक विचार है, लेकिन इस पर कुछ चर्चाओं के अलावा कोई प्रगति नहीं हुई है।

सोने का नहीं बदला भाव, चांदी हुई सस्ती; चेक करें लेटेस्ट प्राइस

परिवहन विशेष न्यूज

अमेरिका से गैर-कृषि पेरोल और बेरोजगारी के महत्वपूर्ण आंकड़े आने वाले हैं। उससे पहले गोल्ड ट्रेडर्स ने अतिरिक्त सतर्कता दिखाई और अधिक खरीदारी या बिक्री से परहेज किया। सोने की कीमत 79150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही। हालांकि चांदी 300 रुपये घटकर 93500 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। आइए जानते हैं कि अब सोना किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

नई दिल्ली। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं, चांदी के भाव में गिरावट आई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 79,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही। हालांकि, चांदी 300 रुपये घटकर 93,500 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। गुरुवार को सफेद धातु 93,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। शुक्रवार को 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत भी 78,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर वायदा कारोबार में फरवरी डिलीवरी वाले सोने के अनुबंधों में 181 रुपये या 0.24 प्रतिशत की तेजी आई और यह 76,657 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो गोल्ड की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।

सोने की कीमतों पर क्या है एक्सपर्ट की राय

एलकेपी सिक्योरिटीज में कमोडिटी और करेंसी के वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने कहा, ₹आज शाम को बाजार में गैर-कृषि पेरोल और बेरोजगारी के महत्वपूर्ण आंकड़ों का इंतजार है। इसलिए एमसीएक्स पर सोने में मामूली बढ़त दर्ज की गई। फेड के नीतिगत दृष्टिकोण को आकार देने के लिए ये मीट्रिक महत्वपूर्ण हैं।"

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, ₹अमेरिका में उम्मीद से बेहतर मैक्रोइकॉनोमिक डेटा फेड को इस महीने दरों में कटौती रोकने के लिए मजबूर कर सकता है। इसका सोने की कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, उम्मीद से कमजोर डेटा सोने की कीमतों में उछाल ला सकता है।"

भू-राजनीतिक तनाव पर भी रहेगी नजर

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के कमोडिटी रिसर्च के विश्लेषक मानव मोदी ने कहा, ₹डॉलर में कमजोरी और शुक्रवार को आने वाली प्रमुख नौकरियों की रिपोर्ट से पहले सोने में स्थिरता बनी हुई है। भू-राजनीतिक अशांति लगातार बढ़ रही है, जिससे सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों के लिए मजबूत आधार तैयार हो रहा है।' फ्रांस की सरकार गिर गई, जबकि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक-योल के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने देश में मार्शल लॉ लागू करने का असफल प्रयास किया था। मोदी ने कहा कि अमेरिका से लगातार कमजोर आंकड़ों की रिपोर्ट के बाद डॉलर में गिरावट आई, जो गोल्ड के लिए अच्छी बात है।

शाबाश डोम्माराजू गुकेश !-18 वर्ष की उम्र में 18 वीं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप सिंगापुर को जीतकर शतरंज की दुनियाँ में तूफान मचा दिया !

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर भारत की बौद्धिक क्षमता का हर क्षेत्र में लोहा पूरी दुनियाँ ने देखा है, जो कुछ वर्षों से पूरे दम ख़म से आगे बढ़कर उच्चस्तर पर रिकॉर्ड बना रहा है, नए-नए अध्याय जुड़ते जा रहे है,चाहे वह प्रौद्योगिकी, संचार, विज्ञान, स्वास्थ्य, स्पेस सहित सभी क्षेत्र से या फिर शिक्षा व खेल क्षेत्र हो, अनेक नवाचार नवोन्मेष से हैरत अंग्रेज सफलताएं मिल रही है, इसी क्रम में दिनांक 12 दिसंबर 2024 को देर शाम सिंगापुर में हो रही 18 वीं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में मात्र 18.6 वर्ष के डोम्माराजू गुकेश ने यह चैंपियनशिप जीतकर शतरंज की दुनियाँ में तूफान मचा दिया है, इतनी कम उम्र में यह जीत दर्ज कर उन्होंने दिखा दिया है कि कैसे एक बच्चा भी बड़े बड़ों को हराकर भारत की झोली में यह जीत का तमगा डालकर अविस्मरणीय नया अध्याय जोड़ सकता है,जो पूरी दुनियाँ के लिए चौकाने वाला हैरत अंग्रेज कारनामा है,इतनी कम उम्र में जो जीत का रिकॉर्ड है, यह मेरा मानना है कि आने वाले 100 वर्षों में भी शायद इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तक रूस के दिग्गज गैरी कास्पारोव सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन थे जिन्होंने आज से 39 वर्ष पूर्व 1985 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में यह ख़िताब उन्होंने जीता था परंतु भारतीय सपूत डी गुकेश ने मात्र 18.6 वर्ष की उम्र में खिताब जीतकर करीब 3.5 वर्ष आगे बढ़ गए हैं जिसे तोड़ना शायद बहुत मुश्किल काम है। चूँकि भारत में चीन को चेस्ट 22 वर्षावाद को हराकर 18.6 वर्ष वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, शाबाश डोम्माराजू गुकेश 18 वर्ष की उम्र में 18 वीं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की जीत कर शतरंज की दुनियाँ में तूफान मचा दिया है।

साथियों बात अगर हम 18 वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप प्रतियोगिता सिंगापुर में भारत के 18 वर्षीय डी गुकेश के इतिहास रचने की करें तो,उन्होंने अपने शानदार खेल से 18 वें वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीतकर इतिहास रच दिया है। डी गुकेश ने सिर्फ 18 साल की उम्र में यह कारनामा कर दिखाया है। ऐसा करने वाले गुकेश दुनियाँ के सबसे युवा ग्रैंडमास्टर बने हैं। गुकेश ने ख़िताबी मुकाबले में चीन के डिंग लिरेन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। डी गुकेश ने चैंपियनशिप मुकाबले के 14 वें और आखिरी राउंड में चीन के चैंपियन डिंग लिरेन को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंतिम बाज़ी भारत के डी गुकेश ने जीतकर ख़िताब को अपने नाम कर लिया गुकेश ने 14 बाज़ी के इस मुकाबले की आखिरी क्लासिकल बाज़ी जीतकर लिरेन के 6.5 के मुकाबले ज़रूरी 7.5 अंक के साथ ख़िताब जीता। यह बाज़ी हालांकि अधिकांश समय ड्रॉ की ओर जाती दिख रही थी। गुकेश की ख़िताबी जीत से पहले रूस के दिग्गज गैरी कास्पारोव सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन थे जिन्होंने 1985 में अनातोली कार्पोव को हराकर 22 साल की उम्र में ख़िताब जीता था।12 साल के बाद किसी भारतीय ने इस ख़िताब को अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले दिग्गज विश्वनाथन आनंद ने 2012 में चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का ख़िताब जीता था। गुकेश यह ख़िताब जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। बुधवार को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की 13 वीं बाज़ी में 68 चाल के बाद गुकेश को गेम ड्रॉ खेलना पड़ा था। तब स्कोर 6.5-6.5 से बराबरी पर था। गुकेश ने तीसरा, 11वां और 14वां गेम जीता। वहीं लिरेन ने पहला और 12 वां गेम जीता। बाकी सभी गेम ड्रॉ रहे। उन्होंने लिरेन को 14वें गेम में से हराया। इसी के साथ स्कोर 7.5-6.5 हो गया और गुकेश चैंपियन बन गए। गुकेश की वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच की यात्रा पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई जब उन्होंने चेन्नई ग्रैंडमास्टर्स टूर्नामेंट जीतकर कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाई थी। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में फाबियानो कारूआना और हिकारु नाकामुरा की अमेरिकी जोड़ी को प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन गुकेश ने सभी को पछाड़ते हुए कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर शतरंज की दुनियाँ में तूफान मचा दिया था और विश्व चैंपियनशिप मुकाबला में जगह बनाई थी। तब गुकेश की उम्र मात्र 17 साल थी। वह कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा प्लेयर थे। शतरंज की दुनियाँ में नया इतिहास रचने वाले डी गुकेश चैंपियन बनते ही फूट-फूट कर रो पड़े, जो ख़िताबी हमेशा शांत दिखता रहा है, वह विश्व चैंपियन बनने के बाद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका। डी गुकेश ने कहा मैं इस जीत को एक उपलब्धि की, जिसका सपना तो सभी देखते हैं, उन्होंने भी देखा था लेकिन वे इतनी जल्दी चैंपियन बन जाएंगे, इसकी उम्मीद नहीं की थी, शायद यही वजह है कि वे आंसू नहीं रोक पाए भारत के डी गुकेश ने गुरुवार को फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल में गत चैंपियन डिंग लिरेन को हराया। दोनों खिलाड़ी एक दिन पहले तक 6.5-6.5 से बराबरी पर थे। गुरुवार को 14वीं बाज़ी खेली गई, जिसमें डिंग लिरेन ने सफेद मोहरों से शुरुआत की, गुकेश ने इस निर्णायक बाज़ी में दबाव पर नियंत्रण रखा और गत चैंपियन को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है।

साथियों बात अगर भारत चीन के खिलाड़ियों के बीच टक्कर शतरंज चालों की करें तो, यह बाज़ी अधिकांश समय ड्रॉ की ओर जाती दिख रही थी। विश्लेषकों ने मैच के टाईब्रेकर में जाने की पूरी संभावना जता दी थी लेकिन गुकेश धीरे-धीरे अपनी स्थिति मज़बूत कर रहे थे। यह लिरेन की एकाग्रता में क्षणिक चूक थी जिससे ड्रॉ की ओर बढ़ रही बाज़ी का नतीजा निकला और जब ऐसा हुआ तो पूरा शतरंज जगत हैरान हो गया।55 वीं चाल में गलती कर बैठे लिरेन, दोनों खिलाड़ियों के पास आखिरी समय में बस एक रूक (हाथी) और एक बिशप (ऊंट) बचा था, जिसे उन्होंने एक दूसरे को गंवाया, अंत में गुकेश के दो प्यादों के मुकाबले लिरेन के पास सिर्फ एक प्यादा बचा था और चीन के खिलाड़ी ने हार मानकर ख़िताब भारतीय खिलाड़ी की झोली में डाल दिया लिरेन ने 55 वीं चाल में गलती की जब उन्होंने हाथी की अदला-बदली की और गुकेश ने तुरंत इसका फायदा उठाया और अगली तीन बाज़ी में मुकाबला खत्म हो गया गुकेश ने गुरुवार को निर्णायक बाज़ी से पहले तीसरे और 11वें दौर में जीत हासिल की थी।32 वर्षीय लिरेन ने शुरुआती बाज़ी के अलावा 12वीं बाज़ी अपने नाम की थी। अन्य सभी बाज़ियां ड्रॉ रहीं

साथियों बात अगर हम डी गुकेश के जीवन व उन्हें मिले पुरस्कारों के बारे में जानने की करें तो, गुकेश डी का पूरा नाम डोम्माराजू गुकेश है। वह चेन्नई के रहने वाले हैं। गुकेश का जन्म चेन्नई में 7 मई 2006 को हुआ था उन्होंने 7 साल की उम्र में ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। उन्हें शुरू में भास्कर नागैया ने कोचिंग दी थी। नागैया इंटरनेशनल चेस खिलाड़ी रहे हैं और चेन्नई में चेस के होम ट्यूटर हैं। इसके बाद विश्वनाथन आनंद ने गुकेश को खेल की जानकारी देने के साथ कोचिंग दी। गुकेश के पिता डॉक्टर हैं और मां पेशे से माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं गुकेश को मिले 11.45 करोड़ रुपए, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के 138 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एशिया के 2 खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन के ख़िताब के लिए आमने-सामने थे। क्लासिकल गेम में एक जीत पर प्लेयर को 1.69 करोड़ रुपए मिले। यानी 3 गेम जीतने पर गुकेश को 5.07 करोड़ और 2 गेम जीतने पर लिरेन को 3.38 करोड़ रुपए सीधे ही मिल गए। बाकी प्राइज़ मनी दोनों प्लेयर्स में बराबर बांटी गई, यानी गुकेश को 11.45 करोड़ और लिरेन को 9.75 करोड़ रुपए का इनाम मिला।

साथियों बात अगर हम डी गुकेश को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री द्वारा दी गई बधाई की करें तो, राष्ट्रपति ने कहा-विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने पर गुकेश को हार्दिक बधाई। उन्होंने भारत को बहुत गौरवान्वित किया है। उनकी जीत शतरंज की महाशक्ति के रूप में भारत की साख को दर्शाती है। गुकेश ने बहुत बढ़िया काम किया है। हर भारतीय की ओर से मैं कामना करती हूं कि आप भविष्य में भी इसी तरह सफल होते रहें प्रधानमंत्री ने आज गुकेश डी को सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर बधाई दी। उन्होंने गुकेश को इस उपलब्धि को ऐतिहासिक और अनुकरणीय बताया एक्स पर अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के हैंडल की एक पोस्ट का जवाब देते हुए,उन्होंने कहा:ऐतिहासिक और अनुकरणीय।गुकेश डी को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई। यह उनकी अद्वितीय प्रतिभा, कड़ी मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प का परिणाम है।उनकी जीत ने न केवल शतरंज के इतिहास में उनका नाम दर्ज कराया है,बल्कि लाखों युवा प्रतिभाओं को बड़े सपने देखने और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित भी किया है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि शाबाश डोम्माराजू गुकेश!-18 वर्ष की उम्र में 18 वीं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप सिंगापुर को जीतकर शतरंज की दुनियाँ में तूफान मचा दिया।भारत के डी गुकेश ने इतिहास रच दिया है। भारत का लोहा पूरी दुनियाँ ने माना-दुनियाँ के यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 18 वर्षीय गुकेश डी ने 18.5 वर्ष का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ने में अब 100 वर्ष लग सकते हैं।

संविधान की 75वीं वर्षगांठ विशेष - संविधान हम सभी के लिए न्याय, एकता, और अभिव्यक्ति के अधिकार की गारंटी

डॉ. बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकती हैं : वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान

हम सभी को बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात कर संविधान में दिए कर्तव्यों और अधिकारों की रक्षा के लिए संकल्पित होना चाहिए

आगरा,संजय साग़र सिंह। पूज्य डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने डॉ. अंबेडकर जी के योगदान और उनके विचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के निर्माण के साथ-साथ समाज में व्याप्त धार्मिक और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ भी संघर्ष किया। उनका जीवन शोषितों, वंचितों, और महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्पित था। डॉ. अंबेडकर जी का दृष्टिकोण यह था कि समाज में समानता और स्वतंत्रता होनी चाहिए, और इसके लिए शिक्षा और संघर्ष की आवश्यकता है। उनका प्रसिद्ध उद्घोष "शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो" आज भी युवाओं को प्रेरित करता है।

मुशरफ खान ने संविधान को सुरक्षा कवच बताते हुए कहा कि यह हम सभी के लिए न्याय, एकता, और अभिव्यक्ति के अधिकार की गारंटी है। उन्होंने संविधान दिए कर्तव्यों और अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया और यह भी बताया कि संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह नैतिक और मौलिक अधिकारों का स्रोत है। वे मानते थे कि धर्मनिरपेक्षता को मजबूत किया जाना चाहिए और हर व्यक्ति को समाज में समान सम्मान और अधिकार मिलने चाहिए।

श्री खान ने डॉ. अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य समाज में जातिवाद और अशिक्षा को समाप्त करना था, और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर भी विशेष ध्यान दिया। वे चाहते थे कि हर नागरिक को समान अधिकार मिलें और यही उनके जीवन का उद्देश्य था। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से न केवल दलितों बल्कि सभी वर्गों को सम्मान और अधिकार देने की बात की।

बैधनाथ ज्योतिर्लिंग में मुख्यमंत्री ने सपत्नीक की पूजा-अर्चना

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

रांची, झारखंड विधासभा का प्रथम सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं उनकी धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने आज देवघर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। पुरोहितों द्वारा पूरे विधि-विधान से बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के गर्भ गृह में शिवलिंग की पूजा-अर्चना संपन्न कराई गई। त्रेता युग में श्रेष्ठ वैदिक ज्ञाता

पंडित रावण के आराध्य देव इस महादेव से मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने झारखंड वासियों की सुख-समृद्धि, उन्नति और खुशहाली की प्रार्थना की।

इससे पूर्व देवघर एयरपोर्ट आगमन पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन का

विधायक, सारठ उदय शंकर सिंह, संथाल परगना

कमिश्नर लालचंद दादेल, संथाल परगना आई.जी. क्रांति कुमार, डी.आई.जी. संजीव कुमार, उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी विशाल सागर, पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग द्वारा स्वागत एवं अभिवादन किया गया। मौके पर जिला प्रशासन देवघर द्वारा एयरपोर्ट परिसर में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया .

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम पर सुनवाई शुरू की, नए मुकदमों पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 12 दिसंबर 2024 को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। इस अधिनियम के तहत, 15 अगस्त 1947 को मौजूद धार्मिक स्थलों की स्थिति को यथावत रखने का प्रावधान है, जिससे उनके धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन पर रोक लगाई जाती है।

मुख्य बातें

- नए मुकदमों पर रोकः अदालत ने निर्देश दिया कि जब तक इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक किसी भी नए मुकदमे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही, लंबित मामलों में भी कोई प्रभावी या अंतिम आदेश पारित नहीं किए जाएंगे।

- सरकार से जवाब:

केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। सभी पक्षकारों को इस हलफनामे की प्रति उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल या अन्य व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया गया है।

- लंबित मामले:

अदालत को सूचित किया गया कि वर्तमान में देशभर में 10 धार्मिक स्थलों से संबंधित 18 मुकदमे विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इनमें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद, संभल में शाही जामा मस्जिद और अजमेर दरगाह शामिल हैं।

अगली सुनवाई:

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है और तब तक स्थिति को यथावत रखने का निर्देश दिया है। सभी पक्षकारों से अपेक्षित है कि वे अपने तर्क पूरी तैयारी के साथ प्रस्तुत करें ताकि मामले का शीघ्र निपटान हो सके। यह निर्णय धार्मिक स्थलों के विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो देश की सामाजिक और धार्मिक एकता को प्रभावित कर सकते हैं।

हानिकारक व्यवहारों में कमी लाते हैं -'सिन-टैक्स'

जीएसटी को 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था और भारत के राष्ट्रपति ने 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय जीएसटी कानून को स्वीकृति दी तथा बाद में 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ। दरअसल, देशभर में टैक्स में एकरूपता लाने और जटिलता दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में ऐतिहासिक जीएसटी व्यवस्था लागू की थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि सीजीएसटी शुल्क केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है। इसी तरह से एसजीएसटी भी है। कहना ग़लत नहीं होगा कि जीएसटी लागू करने का मकसद देश में 'एक देश-एक मार्केट-एक टैक्स' विचार को मूर्तरूप देना था और जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स, वैट, क्रय कर, एक्साइज ड्यूटी और अन्य कई टैक्स समाप्त हो गए और इनकी जगह जीएसटी ने ले ली। उल्लेखनीय है कि आजादी के बाद जीएसटी को सबसे बड़ा कर सुधार माना जाता है। बहरहाल, वर्तमान में सरकार जहां एक ओर रोज़मर्रा की जिन्दगी में काम आने वस्तुओं की जीएसटी दरों को कम करने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर उन चीजों पर टैक्स बढ़ाये जाने पर विचार कर रही है, जिनका उपयोग समाज और देश के साथ ही उपयोग करने वालों के भी हित में नहीं है। वास्तव में इस प्रकार के टैक्स को 'सिन गुड्स टैक्स' कहा जाता है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि वास्तव में, सिन गुड्स वे वस्तुएं होती हैं, जिन्हें समाज के लिए हानिकारक माना जाता है। जैसे- शराब और तंबाकू, फास्ट फूड, कॉफी, चीनी, जुआ और पोर्नोग्राफी। और इस प्रकार की विभिन्न वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर या टैक्स ही 'सिन गुड्स टैक्स' कहलाता है। आज भारत में तंबाकू और इससे जुड़े उत्पादों का उपभोग लगातार बढ़ रहा है। गौरतलब है कि भारत तंबाकू के सेवन और उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और इससे न केवल जान-माल का नुकसान होता है, बल्कि इसके कारण से भारी सामाजिक और आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ती है। तंबाकू से भारत की जीडीपी को भी नुकसान पहुंच रहा है।डब्ल्यूएचओ की हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में सालाना 13 लाख भारतीय तंबाकू से जुड़ी बीमारी से अपनी जान गंवाते हैं। इसी बीच अब भारत सरकार सिगरेट, तंबाकू उत्पादों और कुछ खास ड्रिंक्स पर जीएसटी दर को बढ़ाने जा रही है। इसके तहत इन उत्पादों पर 28 फीसदी जीएसटी को बढ़ाकर 35 फीसदी तक किया जाएगा। गौरतलब है कि मंत्रिमंडलीय समूह द्वारा यह प्रस्ताव जीएसटी ढांचे में सुधार करने के उद्देश्य से दिया गया है, ताकि सरकार का राजस्व बढ़ सके और स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने वाले उत्पादों का सेवन कम हो। यहां कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य स्वस्थ भारत का भी है और तंबाकू मुक्त भारत' उसका एक प्रमुख स्तंभ है। यदि इस जीएसटी प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो कंपनियों को सिगरेट, तंबाकू और कुछ वीवरेज ड्रिंक्स की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। पाठकों को जानकारी देता चलूं कि जीएसटी काउंसिल की बैठक इसी महीने 21 दिसंबर को होने वाली है, उससे पहले जीओएम ने सिगरेट-तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स पर लगने वाले टैक्स को 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है। वास्तव में ऐसा करने के पीछे सरकार का उद्देश्य यह है कि इन उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाने से इनकी खपत में कमी आए और लोग स्वास्थ्य की दृष्टि से इनके सेवन से बचें अथवा इसे कम करें। इसके अलावा, सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि लोग ज्यादा सेहतमंद विकल्पों का चयन करें। यहां यह कहना ग़लत नहीं होगा कि सरकार ने यह कदम राजस्व में वृद्धि लाने के उद्देश्य से उठाया है। इसका परिणाम यह होगा कि इस टैक्स के लागू होने के बाद लोगों को इन सभी उत्पादों के लिए जेब से अधिक खर्च करना पड़ेगा, लेकिन सरकार की मंशा है कि यह स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों का इस्तेमाल कम हो। सरकार का यह कदम वाकई काबिले-तारीफ है। यदि टैक्स बढ़ोत्तरी का यह प्रस्ताव लागू होता है तो इससे कंपनियों की आय व इनके शेयरों पर कहीं न कहीं असर पड़ेगा। बहरहाल, जो भी हो 'सिन-टैक्स' का प्राथमिक लक्ष्य और सकारात्मक प्रभाव अस्वस्थ और सामाजिक रूप से हानिकारक व्यवहारों में कमी लाना है। निश्चित ही 'सिन-टैक्स' व्यक्तियों और समाज दोनों को लाभ प्रदान करने के साथ ही देश को भी लाभान्वित करते है।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर

2025 से एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ: ईपीएफओ का बड़ा कदम, जानिए कैसे होगा फायदा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक ऐसी योजना की घोषणा की है, जो करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। अब आप 2025 से अपने पीएफ (प्रोविडेंट फंड) खाते से सीधे एटीएम के जरिए पैसा निकाल सकेंगे। यह सुविधा कर्मचारियों के लिए फंड की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और उन्हें लंबी प्रक्रिया से राहत दिलाएगी।

कैसे करेगा यह सिस्टम काम ?

ईपीएफओ ने पीएफ खातों को यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम से जोड़ने का फैसला किया है। इस नई व्यवस्था के तहत:

* पीएफ खाते को डेबिट कार्ड या यूपीआई से जोड़ा जाएगा: इससे पीएफ खाता एक सामान्य बैंक खाते की तरह काम करेगा।
* एटीएम पर तुरंत निकासी: कर्मचारी बिना किसी आवेदन प्रक्रिया के सीधे एटीएम से अपने पीएफ खाते का पैसा निकाल सकेंगे।
* सुरक्षित और त्वरित लेन-देन: इस तकनीकी सुविधा से कर्मचारी डिजिटल माध्यम से तुरंत सुरक्षित लेन-देन कर पाएंगे।

अभी क्या है प्रक्रिया ?

वर्तमान में पीएफ की निकासी के लिए कर्मचारियों को ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर आवेदन करना पड़ता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3 से 7 दिन में पैसा उनके खाते में ट्रांसफर होता है। यह प्रक्रिया समय लेने वाली है और कई बार इसमें तकनीकी दिक्कतें भी आती हैं।

क्या होंगे इस नई सुविधा के फायदे ?

* इमरजेंसी में त्वरित सहायता: अचानक जरूरत पड़ने पर पैसा तुरंत उपलब्ध होगा।
* सरल प्रक्रिया: लंबी और जटिल प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलेगा।
* डिजिटल लेन-देन: यह प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित और डिजिटल होगी।
* समय की बचत: कर्मचारियों को फंड निकालने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

कैसे करें तैयारी ?

ईपीएफओ ने इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें रखी हैं:

* आपका पीएफ खाता आधार और पैन से लिंक होना चाहिए।
* खाते की केवाईसी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।

ईपीएफओ जल्द ही इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करेगा।

सरकार का उद्देश्य

सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके फंड तक त्वरित और आसान पहुंच देना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह कदम वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा और आपातकालीन स्थिति में बड़ी मदद साबित होगा।

चुनौतियां भी हैं

हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस नई सुविधा को लागू करने में तकनीकी और लॉजिस्टिक चुनौतियां हो सकती हैं। साथ ही, इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए सभी कर्मचारियों को डिजिटल प्रणाली की जानकारी देना और उन्हें इस पर प्रशिक्षित करना आवश्यक होगा। ईपीएफओ की यह पहल कर्मचारियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। 2025 से लागू होने वाली यह सुविधा न केवल पीएफ निकासी को सरल बनाएगी, बल्कि डिजिटल भारत की दिशा में एक और कदम होगी। यह कदम कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और त्वरित सहायता प्रदान करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

सरायकेला डी एम ओ ने पुनः जप्त की चौदह हजार सी एफ टी अवैध बालू

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

ईचागढ़। शुक्रवार सुबह- सुबह जिला खनन विभाग की टीम के तेज तर्रार मुखिया ज्योति शंकर शतपथी ने चांडिल के अंचल अधिकारी व चांडिल थाना की पुलिस को लेकर छापामारी की । जहां पुनः उन्होंने सफलता की नई मिसाल कायम की है । अगल-अलग स्थानों में चलाए गए छापामारी अभियान में टीम को अपार सफलता हाथ लगी है. जिला खनन विभाग को सूचना मिली थी कि चांडिल थाना क्षेत्र में बालू का अवैध कारोबार पुनः श्री गणेश हो रहा है । ऐसे में क्षेत्र में यदा कदा बालू का अवैध भंडारण किया जा रहा है. इसके बाद सरायकेला-खरसावां जिला के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के निर्देश पर जिला खनन पदाधिकारी

ज्योतिशंकर सतपथी के नेतृत्व में विभागीय टीम शुक्रवार को छापामारी किया जहां चांडिल के अंचल अधिकारी और चांडिल थाना की पुलिस भी रही ।

माइनिंग टीम ने शहरबेड़ा, इसके बाद चिलगु में और अंत में गौरी घाट पर बालू के अवेध कारोबार के खिलाफ छापामारी की गई. चांडिल थाना क्षेत्र के शहरबेड़ा में अवैध रूप से बालू ले जाते एक ट्रैक्टर और एक 407 माल वाहक वाहन को जब्त किया गया है. वहीं अभियान के दौरान शहरबेड़ा में ही दो स्थानों में अवैध रूप से भंडारण कर रखे गए बालू भी जब्त किया गया है. एक स्थान पर करीब नौ हजार सीएफटी और एक स्थान पर करीब पांच हजार सीएफटी बालू जब्त किया है ।

सर्राफा की दुकान में लगी आग पर सिविल डिफेंस और पुलीस ने पाया आग पर काबू

परिवहन विशेष न्यूज

मथुरा: सौंख कस्बे के मुख्य बाजार स्थित सब्जी मंडी में महेश वर्मा की सर्राफा की दुकान हे। दुकान में कारीगर शकील सोने के आभूषणों को उजालने का कार्य करता है । बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 11: 30 कारीगर शेख शकील सोने की आभूषणों को उजालकर सफाई कर रहा था अभी आभूषणों में से तेजाब की एक बूंद जलती आग में तेजी से गिरी जिसके चलते आग के शोले भड़क गए और कारीगर जब तक कुछ समझता, आचनक आग से दुकान में काम कर रहे तीनों कर्मचारी आग की चपेट में आ गए आग लगने से कारीगरों के कपड़े जल गए आग से झुलसे एक कारीगर ने बाहर भाग कर शोर मचाया। दुकान में लगी आग और शोर को सुनकर बाजार में भगदड़ मच गई। बाजार में दुकानें होने लगी। इसी समय नागरिक सुरक्षा विभाग मथुरा के पोस्ट वार्डन और सेक्टर वार्डन राम सैनी, शुभम्‌कुमार कुछ काम से मार्केट आए हुऐ थे तभी देखा कि आग लगने का शोर मच रहा है तभी पोस्ट वार्डन अशोक यादव मौके पर पहुंच गए । चौकी प्रभारी रवेंद्र सिंह भी मौके पर आ गए उनकी मदद से दोनों कारीगरों को दुकान से बाहर निकाल कर घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से नजदीकी हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया। पोस्ट वार्डन अशोक यादव अभी हाल ही मे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नागपुर और राज्य आपदा मोचन बल लखनऊ से फायर और आपदा का कोर्स करके आए अपनी टीम के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया। आग पर काबू पाने के बाद स्थानीय बाजार के लोगों ने सिविल डिफेंस मथुरा की प्रशंसा करते हुए नजर आए।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023